



सत्यमेव जयते

लघु उद्योग समाचार

Laghu Udyog Samachar

जून-नवम्बर / June-November, 2017



MSME SAMADHAAN

लघु उद्यम संवाद

लघु उद्योग समाचार (मासिक)

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने और अपनी प्रति
मंगाने के लिए इस पते पर संपर्क करें:

प्रकाशन नियंत्रक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स
दिल्ली-110054

Controller of Publications
Government of India
Publication Division
Ministry of Urban Development
Civil Lines
Delhi-110054



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का जर्नल

लघु उद्योग समाचार

LAGHU UDYOG SAMACHAR

A Monthly Journal for Micro, Small & Medium Enterprises

विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार का प्रकाशन

A Publication of Development Commissioner (MSME)
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Government of India

वर्ष 42-43 अंक 11-4
मूल्य : 25 रुपये
जून-नवम्बर, 2017
संयुक्तांक/विशेषांक

Volume 42-43 Issue 11-4
Price : ₹ 25
June-November, 2017
Combined/Special Issue

अनुदेश

प्रकाशन के लिए सामग्री डबल स्पेस में स्वच्छ टाइप की हुई तीन प्रतियों में होनी चाहिए। समारोह, घटना आदि के सम्पन्न होने के पश्चात रिपोर्ट तुरन्त ही भेज देनी चाहिए। आलेख/रिपोर्ट के साथ यथासंभव फोटोग्राफ भी भेजे जाने चाहिए, जिनमें चित्र को पत्र के साथ जैमक्लिप लगाकर भेजना चाहिए। फोटोग्राफ में अधिक ध्यान घटना या उत्पाद विशेष आदि पर दिया जाना चाहिए न कि व्यक्ति विशेष पर।

सूचनाओं के सही और विश्वसनीय प्रकाशन में यथा संभव सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी भूल, गलती, त्रुटि या विलोपन के लिए लघु उद्योग समाचार पत्रिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लघु उद्योग समाचार जर्नल में प्रकाशित समाचारों, तस्वीरों तथा दृष्टिकोणों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सरकार की सहमति होना आवश्यक नहीं है।

Instructions

The material for publication should be sent, in triplicate, neatly typed in double space. The reports on functions or events should be sent immediately after its conclusion. Articles/Reports should be accompanied by photographs with captions pasted upon reverse. The photographs should be placed in between the thick paper, gem clipped and attached to the forwarding letter. Photographs should be focussed more on the events or products than personalities.

Disclaimer

All efforts have been made to ensure that the information published is correct and reliable. However, the Laghu Udyog Samachar journal holds no responsibility for any inadvertent error, commission or omission. Opinions, photographs and views published in Laghu Udyog Samachar journal do not necessarily reflect the views of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises or Government.

Harendra Pratap Singh
Chief Editor
Dr. Harish Yadav
Assistant Editor

Editorial Office : Advertising & Publicity Division

Office of the Development Commissioner (MSME)
Nirman Bhavan, New Delhi-110108
Phone & Fax : 011-23062219

Published by Development Commissioner (MSME),

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises,
Government of India, Nirman Bhavan,
New Delhi-110108
www.dcmsme.gov.in



एमएसएमई एक्सपो

मेला या प्रदर्शनी बहुपयोगी उत्पादों की सूचना को बहुजन तक पहुँचाने का एक प्रमुख प्रभावकारी माध्यम है जो सर्वजन तक पहुँचने के अनेक रास्ते दिखाता है। इसीलिए इसे लघु उद्यम संवाद का एक प्रमुख संवाहक भी कहते हैं। इससे प्रदर्शक और दर्शक दोनों लाभान्वित होते हैं और एक-दूसरे को जानने-समझने के लिए करीब आते हैं।

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के दर्शन से युक्त भारत में मेला लोगों को सकारात्मक सोच से लैस करता है और सबका साथ, सबका-विकास की तर्ज पर स्वयं और देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस तरह के मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो विश्व को बाजार और बाजार को वैश्विकता प्रदान करता है। इसी का एक जीवंत नमूना है- आईआईटीएफ, और उसमें नये उदाहरण पेश करने वाला एमएसएमई-एक्सपो!

आईये, इस एक्सपो के बहाने भारत के उद्यम-विकास का अवलोकन करें, और ‘न्यू इंडिया’ के सपने को साकार करने की दिशा में स्व की भागीदारी को भी सार्थक बनायें! वैसे, इस तरह के मेले देश-विदेश के बाजार और उत्पाद को समझने के मौके के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और राष्ट्रों की संस्कृति को भी जानने का सुखद अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति के लिए इसमें बहुत कुछ है। युवाओं के लिए तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है! वैसे देश में शायद ही कोई महीना हो जब कोई मेला न लगा हो, और उसमें कोई उद्यमी भाग न ले रहा हो। अतः मेले को एक उद्यमी और एक दर्शक के नजरिये से आयोजित करने-समझने की जरूरत है। इसी में आयोजन की सार्थकता अंतर्निहित है।

नई दिल्ली
दिनांक : 14.11.2017

हरेन्द्र प्रताप
(हरेन्द्र प्रताप सिंह)

विषय-सूची/CONTENTS

एमएसएमई में विकास का नया दौर	- हरेन्द्र प्रताप	3
ग्रामीण बिहार में लघु उद्यम की अपार संभावना!	- नित्यानन्द नेपाली	9
ऐसा रहा एमएसएमई का मेला !	- के. शुभम मिश्रा	15
भ्रष्टाचार : समस्या एवं निवारण	- अनिल कुमार	23
समाचार		24
फोटो फीचर		32
Photo Feature		34
Marketing Promotion – A need for MSME Sector	- S.R. Samuel and A.K. Verma	36
Indian Polymer Packaging Industry	- Nishant Jain, Sidharth Sirohi, Balaram Pani	39
Celebration of First United Nations Micro, Small and Medium – sized Enterprises Day and distribution of National Awards-2015	- Dr. Om Parkash Mehta	43
Waste Human Hair converted into Novel Agro Nutrients Project Implemented by MGIRI	- Dr. K.R. Yadav	49
Trade Fair/VDP – an initiative of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises to provide marketing support/platform to MSEs	- H.S. Bisht	52
News		56
Vigilance		71



एमएसएमई में विकास का नया दौर

- हरेन्द्र प्रताप

हाल ही में, भारत सरकार ने देश में एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। विनिर्माण क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एमएसएमई क्षेत्र, प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देश में कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। विभिन्न स्थानीय और वैश्विक कारक क्षेत्र के विकास में बाधक बनते हैं। निधि की उच्च लागत, कुशल श्रमशक्ति की कमी, विपणन का बदलता परिदृश्य आदि एमएसएमई के कार्य में बदलाव ला रहे हैं। एमएसएमई को आधुनिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार रखने की जरूरत है। अपनी ओर से सरकार सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र को आवश्यक समर्थन प्रदान कर रही है।

एमएसएमई विनिर्माण, उत्पादन, विकास एवं रोजगार का दायित्व वहन करते हुए अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। सरकार इस क्षेत्र को बहुत महत्व देती है। यह इस बात से भी पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के विकास में बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर एमएसएमई, कॅयर क्षेत्र, केवीआईसी क्षेत्र का मार्गदर्शन किया है।

एमएसएमई के सफल उद्यमियों की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने उद्यमिता में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस घोषित किया है, जिससे इस क्षेत्र के महत्व का पता चलता है।

हाल ही में, भारत सरकार ने देश में एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। विनिर्माण क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एमएसएमई क्षेत्र, प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देश में कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। हालांकि विभिन्न स्थानीय और वैश्विक कारक क्षेत्र के विकास में

बाधक बनते हैं। निधि की उच्च लागत, कुशल श्रमशक्ति की कमी, विपणन का बदलता परिदृश्य आदि एमएसएमई के कार्य में बदलाव ला रहे हैं। एमएसएमई को आधुनिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार रखने की जरूरत है। अपनी ओर से सरकार सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र को आवश्यक समर्थन प्रदान कर रही है।

2016-17 के दौरान 490 करोड़ रु. के परिव्यय से आरंभ की गई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के प्रयास के पीछे समग्र विकास के लिए सरकार की मुहिम रही है।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय-एमएसएमई विकास संस्थान और टूल रूम, पूरे भारत में अपनी सेवाओं से उद्यमियों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने क्षेत्र के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऐसी ही पहल है। पीएमईजीपी के आधार को विस्तार देने के उद्देश्य से

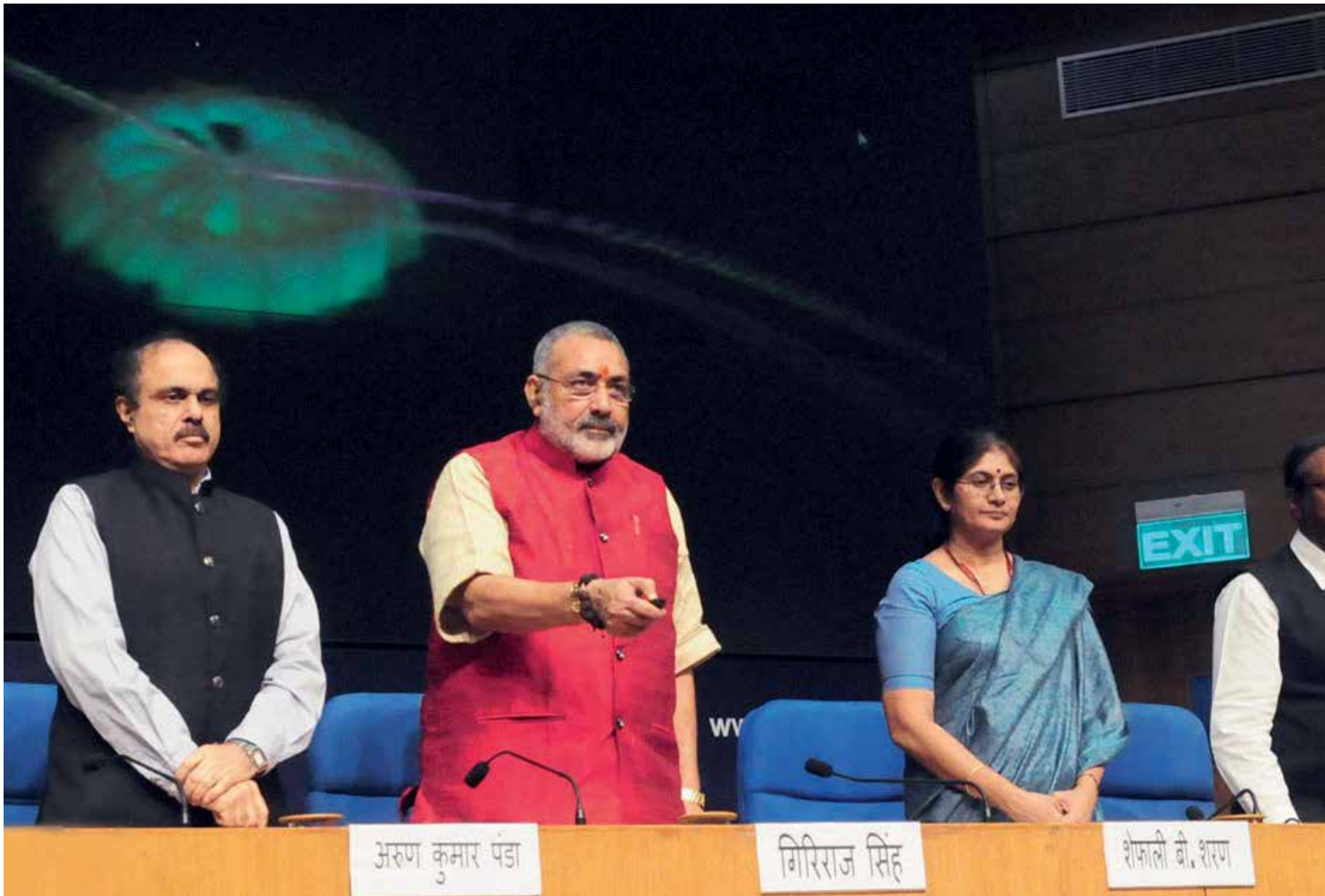


मंत्रालय ने पीएमईजीपी के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। सूक्ष्म उद्यमों की व्यापक कवरेज को सक्षम बनाने तथा सकल वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पीएमईजीपी के लिए प्रति जिला 75 परियोजनाओं का लक्ष्य तय किया गया है। पीएमईजीपी इकाइयों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए केवीआईसी द्वारा एक विशिष्ट वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता सुधार, आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण, विपणन संवर्धन और कॅयर उद्योग में लगे सभी लोगों के कल्याण के उद्देश्य से कॅयर उद्योग के समग्र और निरंतर विकास के लिए कॅयर बोर्ड स्थापित किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुसंधान करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन संचालित करने, कॅयर के अनुप्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विविधकृत उत्पाद और मशीनरी विकसित

करने तथा इको फ्रेंडली प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान, कल्लावूर और केंद्रीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरु की स्थापना की गई है।

एमएसएमई मंत्रालय, एस्पायर (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना) भी कार्यान्वित कर रहा है यह योजना 201 करोड़ रु. के फंड से उद्यमिता को गति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों और इंक्यूबेशन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने तथा साथ ही ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग में नवप्रवर्तन और उद्यमिता के लिए नई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना में 31 मार्च, 2017 तक 25 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर और 5 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जा चुके हैं।



एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के विभिन्न घटक हैं जो विचारों के इंक्यूबेशन से लेकर डिजाइनों, लीन विनिर्माण, ऊर्जा कुशलता, आईसीटी का प्रयोग और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा तक के विनिर्माण के सभी पहलुओं को छूते हैं।

एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का महत्व उन उद्यमियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है जिन्होंने निष्ठापूर्वक प्रयास कर अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार किया है और इससे वे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की चुनौतियों का सामना करने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं। यह जानना उत्साहवर्धक है कि किस तरह एमएसएमई ने इतना विकास किया है और ऐसे

ऊंचे मानदंड स्थापित किए हैं कि उनके उत्पादों को विश्व भर में स्वीकार किया जा रहा है और सराहा जा रहा है।

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और रोजगार सृजन के मुख्य घटकों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार सफलता हासिल करने के बाद भी भारतीय एमएसएमई क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पारंपरिक समस्याओं के अलावा, एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए, भारत में अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए अन्य क्षेत्रों की तरह एमएसएमई को भी हर तरह का उपाय करना होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग उन महत्वपूर्ण उपायों में से एक है, जो एमएसएमई को व्यापार के लगभग हर पहलू में मदद कर सकता है। आईसीटी ने कई प्रकार से व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बना



जून-नवम्बर, 2017

5



दिया है। यह प्रतिस्पर्धात्मकता, बेहतर उत्पाद और सेवा वितरण, प्रक्रिया लागत कम करने और प्रबंधन सूचना प्रणालियों (एमआईएस) का समर्थन करने में एक प्रमुख सहायक बन गई है। कुछ मामलों में, आईसीटी व्यापार मॉडल के केंद्र में रहा है जिससे व्यवसाय के नए तरीकों की समझ का विकास हुआ है। सामान्य तौर पर, किसी भी ऐसे उद्यम को वैश्विक परिवेश में बनाए रखने या विकसित करने के लिए आईसीटी अनुप्रयोग आवश्यक हो गए हैं। आईसीटी को अपनाने से इंडस्ट्री 4.0 मानदंड के निकट आने का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत में एमएसएमई देश के कोने-कोने में फैले उद्यमों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। एमएसएमई उद्यमिता एवं नवोन्मेष के लिए नर्सरी है तथा

स्थानीय बाजारों और वैश्विक बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शृंखलाओं के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की विभिन्न श्रेणियां प्रस्तुत करते हैं।

भारत को एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने और जीडीपी वृद्धि दर को दो अंकों में पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का विजन देश के एमएसएमई के विकास से ही संभव है। एमएसएमई क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' के संदर्भ में जो प्रमुख भूमिका निभाता है उसकी कल्पना जीडीपी में इसके योगदान, विनिर्मित उत्पादों, निर्यात और रोजगार सृजन से लगाया जा सकता है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र अपने आकार, प्रौद्योगिकीय स्तर, उत्पादों की रेंज, ऑटो कंपोनेंट, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रो-मेडिकल डिवाइस के संदर्भ में विविधतापूर्ण है। हालांकि एमएसएमई





क्षेत्र के समक्ष ऋण की उपलब्धता, आधुनिक प्रौद्योगिकी, कुशल श्रमशक्ति, मार्केटिंग के अवसर और आधारभूत संरचना सुविधाओं के अभाव जैसी विभिन्न बाधाएं हैं।

एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की इन बाधाओं से निपटने के लिए और उनके लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है—जैसे एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय अनु.जा./अनु.ज.जा.हब, पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, उद्यमिता एवं ग्रामीण उद्योग संवर्धन की योजना (एस्पायर), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) इत्यादि।

सरकार व्यवसाय करने की सरलता और उद्यमियों के विकास को प्रोत्साहित करने पर फोकस कर रही है। व्यवसाय करने की सरलता के लिए उद्योग आधार ज्ञापन को लागू किया गया है। उद्योग आधार ज्ञापन बिना किसी सहयोगी दस्तावेज और शुल्क के स्व-घोषणा आधार पर ऑनलाइन फाइल की जाने वाली सरलीकृत व्यवस्था है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूचना प्रौद्योगिकी के

अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया है और इसीलिए डिजिटल इंडिया पहल लांच किया गया है। इस दिशा में मंत्रालय निरंतर कार्य कर रहा है। एमएसएमई समाधान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब एमएसएमई सम्बंध की दिशा में तैयारी चल रही है।

विभिन्न योजनाओं के तहत मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं जिसे पीएमईजीपी योजना के शुरू होने के बाद से अब तक हुई राशि की अधिकतम उपयोगिता से देखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 1280 करोड़ रुपए का उपयोग करते हुए 52,912 उद्यम स्थापित किए गए हैं। सीएलसीएसएस के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में 1027.82 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 16,304 एमएसई लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2016-17 में एनएसआईसी ने 11 लाख टन से अधिक की कच्चे माल हेतु सहायता प्रदान की है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कॅयर और कॅयर उत्पादों के निर्यात को 2 हजार करोड़ रुपए के रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने की आशा है। खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री भी क्रमशः 1300 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा पहुंची हैं।

यह मंत्रालय 18 टूल रूमों तथा प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों के माध्यम से हाई एंड स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 8 नए प्रौद्योगिकी

एमएसएमई के विकास में आसानी से ऋण की उपलब्धता प्रमुख बाधा रही है। इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिना किसी कोलेटरल/तृतीय पक्ष की गारंटी के एक करोड़ रुपये तक के ऋण को बढ़ाकर 2 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वित्तपोषण को सुलभ बनाने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं जैसे - मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त पोषण एजेंसी), सिडबी, मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड, स्टैंड अप इंडिया, एस्पायर के तहत निधियों की निधि और स्टार्ट अप इंडिया।

केन्द्रों का कार्य शुरू हो चुका है। 76 प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने एनएसक्यूएफ अनुपालन प्राप्त कर लिया है और लगभग 1,49,000 से अधिक युवाओं को मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षित किया गया है।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए चार समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा संचालित किए जाने हैं।

एमएसएमई के विकास में आसानी से ऋण की उपलब्धता प्रमुख बाधा रही है। इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिना किसी कोलेटरल/तृतीय पक्ष की गारंटी के एक करोड़ रुपये तक के ऋण को बढ़ाकर 2 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वित्तपोषण को सुलभ बनाने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं जैसे - मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त पोषण एजेंसी), सिडबी, मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड, स्टैंड अप इंडिया, एस्पायर के तहत निधियों की निधि और स्टार्ट अप इंडिया।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पास क्लस्टरों के लिए आवश्यक परीक्षण केंद्र, महत्वपूर्ण मशीनरी आदि स्थापित करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं होती है। मंत्रालय एमएसई क्लस्टरों की नैदानिक समस्याओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करता है और 15 करोड़ रुपये की लागत तक की परियोजना के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक की सहायता देता है। यह देश भर में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए काफी लोकप्रिय स्कीम है। अन्य राज्यों में 70 प्रतिशत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों के लिए अधिकतम

सीमा (परियोजना लागत का) 90 प्रतिशत है।

व्यवसाय करने की सरलता के लिए मंत्रालय ने वेब आधारित 'माई एमएसएमई' नामक एक नई पहल की है। इस एप्लीकेशन से एमएसएमई देश के किसी भी हिस्से में बैठे-बैठे अपने प्रस्तावों की प्रगति पर नजर रख सकते हैं और इस एप्लीकेशन के जरिए सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं और शीघ्रताशीघ्र स्कीम का लाभ पा सकते हैं। इस तरह देश में सम्पूर्ण एमएसएमई क्षेत्र में विकास का नया दौर आरंभ हो चुका है। सरकार के साथ-साथ उद्यमियों और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं की अपेक्षित सक्रियता इस क्षेत्र की मंजिल की राह को आसान बना सकती है।

- लेखक इस पत्रिका के मुख्य संपादक हैं और नवभारत टाइम्स में वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं।



ग्रामीण बिहार में लघु उद्यम की अपार संभावना!

- नित्यानन्द नेपाली

आंकड़े बताते हैं कि सम्पूर्ण भारत में लगभग 707 जिले हैं और वर्तमान में बिहार राज्य में 38 जिले हैं। कमोबेश सभी जिले की लगभग एक जैसी ही स्थिति है। तकरीबन हर जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित है, जो राज्य सरकार की ओर से संचालित है।

भारत के मानचित्र पर प्राचीनकाल से ही बिहार राज्य अपनी विशेष पहचान के लिए मशहूर है। राज्य में जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है— वहीं कोसी नदी की अभिशप्त जलधारा भयंकर बाढ़ और

भीषण कटाव जैसी प्राकृतिक आपदा भी उपस्थित करती है। अनेक मनोरम स्थल भी यहां हैं तो अनेक नयनाभिराम तीर्थस्थल भी इस राज्य की गरिमा को बढ़ाते हैं। किन्तु इस राज्य के पीछे दुर्भाग्य भी कमर कसकर घात लगाए



जून-नवम्बर, 2017

9



#startupindia

हमेशा बैठा रहता है, वह है अतिवृष्टि से भीषण बाढ़ और अनावृष्टि से सूखा-अकाल। जब से इस राज्य की सीमा को काटकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई- तब से यह राज्य और भी कंगाल हो गया। जहां एक तरफ-बंजर, परती, उबर-खाबर खेत के अलावा जल ग्रहण क्षेत्र की सीमा में आनेवाली बाढ़ग्रस्त भूमि ही बच गई। सिंचाई का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं होने के कारण यहाँ के किसान और खेतिहर मजदूर अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। युवकों में बेरोजगारी फैल गई। परिणामस्वरूप यहां की जनता रोजगार की तलाश में दूसरे पड़ोसी समृद्ध राज्यों की ओर तेजी से पलायन करने लगी। नजारा यह है कि देश के तमाम राज्यों में बिहारी बेरोजगार लोगों की लंबी कतार लग गई। पूंजीपतियों द्वारा देश के कोने-कोने में संचालित उद्योगों में बिहारी कामगारों का भरपूर शोषण किया जाना एक नियति बन गई। रोजगार के पर्याप्त अवसर का अभाव, एकमात्र कृषि पर आश्रित यहां के लोग अतिवृष्टि और अनावृष्टि का दंश झेलकर हताश और निराश हो दर-दर भटकने पर मजबूर हो गए। बड़े उद्यमों की तो बात ही अलग है- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का भी यहां अभाव है जबकि संभावना अपार है!

शुभ संकेत यह है कि राज्य सरकार आसन्न समस्याओं से निबटने के लिए अनेक कारगर कदम उठा रही है। राज्य से कामगारों का पलायन रूके, बेरोजगारी दूर की जाए- इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम आने की संभावना आने वाले दिनों में सुनिश्चित है।

उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि वर्तमान भौगोलिक परिवेश के आधार पर इस राज्य के हिस्से में मात्र कृषि ही हस्तगत है तो क्यों न कोई सार्थक पहल करके यहाँ की अविकसित कृषि के स्तर को सुधारकर कृषि को उद्यम का दर्जा दिया जाए। अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर, सिंचाई का उत्तम प्रबंधन करके, जैसे- देश के अन्य राज्यों में कृषि स्तर को काफी विकसित किया गया है, ठीक वैसा ही उदाहरण योग्य बनाना इस राज्य के सामने एक अहम् चुनौती है। इन दिनों राज्य के पास जो ज्वलंत प्रश्न हैं- जब तक उसका समाधान नहीं हो पाता अर्थात् जब तक यहां

की कृषि को उद्यम का दर्जा नहीं दिया जाता- तब तक इस राज्य की दिशा और दशा नहीं बदल सकती। आंकड़े बताते हैं कि सम्पूर्ण भारत में लगभग 707 जिले हैं और वर्तमान में बिहार राज्य में 38 जिले हैं। कमोवेश सभी जिले की लगभग एक जैसी ही स्थिति है। तकरीबन हर जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित है, जो राज्य सरकार की ओर से संचालित है। अन्य राज्यों जैसे- महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में भी वहां की राज्य सरकारों की ओर से हर जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो इन राज्यों के जिला उद्योग केन्द्रों का स्तर काफी उत्तम है। वहाँ के जिला उद्योग केन्द्र, वहाँ की जनता की बेरोजगारी को, अभावों को दूर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में अति विचारणीय पहलू उभरकर सामने आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिनों बाद भी किसानों और खेतिहर मजदूरों, कामगारों, बेरोजगार युवकों, महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ पाया है। हां इस संदर्भ में यदि देखा जाये जो राज्य सरकार की ओर से हाल के दिनों में- नशाबंदी अभियान चलाकर, ग्रामीण सड़कों का विकास करके, बिजली की बिगड़ी हुई व्यवस्था में सुधार करके उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं- यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती हैं। किन्तु असली समस्याओं के समाधान की दिशा में राज्य सरकार को दो महत्वपूर्ण कदम अवश्य ही उठाने की आवश्यकता है- प्रथम तो राज्य की कृषि को उद्यम का दर्जा देना और दूसरा है- यहां के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को समृद्ध किया जाए तो अतिशीघ्र ही इस राज्य की काया पलट सकती है। केवल राज्य ही नहीं वरन् राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाय तो अपना देश भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग एक अरब तीस करोड़ जनता के भोजन का प्रबंध किसान और खेतिहर मजदूर ही करते हैं। वे ही अन्नदाता हैं। फिर भी इस स्वतंत्र देश में यदि किसी वर्ग की सबसे अधिक उपेक्षा की जाती है तो वह है किसान और खेतिहर मजदूर!

बतौर स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से परिभ्रमण के दौरान मेरी मुलाकात मुंगेर जिला के एक प्रबुद्ध व्यक्ति श्री विभास कुमार सिंह से हुई। इनसे मुझे जो धरातलीय जानकारियां प्राप्त हुईं- वह इस प्रकार हैं- ये एक पढ़े-लिखे,

लघु उद्योग समाचार



समझदार और जिम्मेदार नागरिक हैं। इतिहास से एम.ए. हैं। प्रारंभ में इन्होंने सरकारी नौकरी पाने का अथक प्रयास किया। किन्तु इन्हें सफलता नहीं मिली। तब इन्होंने कृषि कार्य में अपनी किस्मत को आजमाना शुरू किया। इस राह में इन्हें बेशुमार कठिनाइयां आईं तो— किंकर्तव्यविमूढ़ता होना स्वाभाविक है। पढ़-लिखकर कुछ करने की भरपूर तमन्ना लिए ये भहकते रहे।

युवाकाल से ही बेरोजगारी और अभावों के दंश से पीड़ित होकर अब ये प्रौढ़ हो गए हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ीं तो किंकर्तव्यविमूढ़ता को झटक कर घर पर ही कोई निजी उद्यम स्थापित करने का मन बनाया। बस, क्या था— शिक्षित बेरोजगार की पूंछ तो लगी ही थी, अतएव रोजगार के लिए ऋण मुहैया हेतु बैंकों का चक्कर लगाने लगे। इनके पांवों की एड़ी तो घिस गई, छाले पड़ गए किन्तु बैंक के भ्रष्ट पदाधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक तो बेरोजगार उस पर पारिवारिक जिम्मेदारियां, अभावों का जीवन, एकदम साधन विपन्न होने के कारण भला, रिश्वत की मांग होने के कारण इनका हौसला ही पस्त कर दिया। बैंक से निराशा मिलने के बाद इन्होंने मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र की ओर रूख किया। शायद, इस आशा से कि वहां पर ही कोई समुचित समाधान निकल जाए। पर्याप्त संसाधन के अभाव में जिला उद्योग केन्द्र की ओर से इन्हें कुछ सुझाव तो अवश्य मिले किन्तु वहां भी इन्हें निराशा ही मिली। वर्तमान में मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र जिन समस्याओं को झेल रहा है जिसके कारण केन्द्र रोजगारोन्मुख बेरोजगार लोगों की मदद करने में अक्षम हो रहा है— उसका खुलासा यह है कि केन्द्र की ओर से पूर्व में जितने भी उद्यमी रोजगार के नाम पर बैंक से कर्ज लिए उसकी समय पर अदायगी न होने के कारण आगे की कार्यप्रणाली में भरपूर गतिरोध आ गया है। जब बैंक और केन्द्र के बीच उचित तालमेल ही लड़खड़ा गया हो तो वहां निदान कतई संभव नहीं है।

अतः राज्य सरकार की ओर से कोई सार्थक पहल करके बैंकों और केन्द्र के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास अपेक्षित है। ऋणधारकों को भी अपनी संकीर्ण मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है— तभी वर्तमान पीढ़ी के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार सृजन कर आत्मनिर्भर होने का मौका हासिल हो सकेगा।

इनकी आपबीती सुनने के बाद यह जिज्ञासा जगी कि क्यों न मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र जाकर वहां की वस्तुस्थिति का जायजा लिया जाए। शायद, कोई ठोस तथ्य उजागर हो सके। इसी क्रम में मैं बतौर स्वतंत्र पत्रकार मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र के प्रभारी महाप्रबंधक इंजीनियर सत्येन्द्र कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात करने पहुंचा तो उनके द्वारा



जिले में उद्यम और उद्योग के बारे में दिलचस्प सुझाव और तथ्य प्राप्त हुए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत, मुंगेर जिला के विभिन्न बैंकों द्वारा जिला टास्क फोर्स समिति से चयनित आवेदकों को उद्यम लगाने हेतु ऋण भुगतान किए गए। पिछले पांच सालों में पी.एम.ई.जी.पी. योजना के अर्न्तगत लगभग 150 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत लाभान्वित आवेदकों द्वारा



स्थापित किए गए उद्यम का भौतिक सत्यापन शत-प्रतिशत नहीं होने के कारण वर्तमान में कुछ उद्यम अपनी मूल परियोजना में नहीं आ पाये हैं। बैंक के द्वारा अधिकांशतः उन आवेदकों को ही ऋण देने की कोशिश की जा रही है जो पूर्व से ही उन कार्यों को कर रहे हैं। यह भी निर्देश सीमा का उल्लंघन है।

जिला में सूक्ष्म उद्यम की ही स्थापना हो पाई है जबकि लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित नहीं हो पाए हैं। अतएव विचारणीय मुद्दा है कि लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना निकट भविष्य में अपेक्षित है। इसके लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकता है।

मुंगेर जिला में मसाला, गेहूं का आटा, गेटग्रील उद्योग, कृषियंत्र, सीमेंट उत्पाद, कॉर्नफ्लैक्स, दालमोट मिक्सचर, पैकेज, ड्रिंकिंग वाटर का उद्यम, आइस ब्लॉक एवं आइसक्रीम निर्माण उद्योग, बेकरी उद्योग, बैटरी वाटर उद्योग, काष्ठ प्लम्बिंग, सेवा उद्योग, फर्नीचर निर्माण उद्योग, स्टील फर्नीचर निर्माण उद्योग, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर रिपेयरिंग एवं सर्विसेज, रेस्टोरेन्ट, प्रिन्टिंग वर्क्स, सिलवर ज्वेलरी इकाई, मस्टर्डऑयल मिल, राँ राइस मिल, चूड़ा

उद्योग, राइस पफ (मूढ़ी) उद्योग, नमकीन उद्योग, रेल कम्पोनेट निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल सर्विस इकाई, कूलर निर्माण उद्योग, स्वाइल पौटरी (मिट्टी का बर्तन) निर्माण उद्योग, ईट निर्माण उद्योग आदि सूक्ष्म उद्यम संचालित हैं। किन्तु वित्तपोषण के अभाव में सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। लघु उद्योग की स्थापना हेतु उद्यमता विकास कार्यक्रम एवं बैंकों का वित्तपोषण के मामले में सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।

वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी को स्वयं का उद्यम लगाने हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकता है।

जिला स्तर पर लघु उद्योग से सम्बन्धित प्रकाशन और सूचना का एक ऐसा केन्द्र होना चाहिए जहां पर भावी उद्यमियों द्वारा अध्ययन किया जा सके। साथ ही विभिन्न लघु उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों एवं यंत्रों की जानकारी मिल सके ताकि निर्माण प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा देखा जा सके। महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए इन्होंने अपने अनुभव का हवाला इस प्रकार दिया:-

लघु उद्योग समाचार

प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में लघु उद्योग से सम्बन्धित किताबें, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक परियोजना से सम्बन्धित किताबें, लघु उद्योग से सम्बन्धित मशीन एवं यंत्रों का होना अति आवश्यक है। एक लाइब्रेरी सह प्रदर्शन केन्द्र भी अवश्य होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवश्य हो जिससे निर्माण प्रक्रिया का प्रदर्शन स्क्रीन पर उतर सके।

सूक्ष्म और लघु उद्योग उद्यम चला रहे उद्यमियों के लिए उनकी समस्याओं के निवारण हेतु एवं उद्योग के सुचारू रूपेण संचालन हेतु कम से कम तीन दिन का वर्कशॉप या सेमिनार का क्रम जिला स्तर पर वर्ष में तीन बार अवश्य ही होना चाहिए। उच्च विद्यालय स्तर से इन्टरमीडियट स्तर के विद्यालय में उद्योग एवं उसकी स्थापना से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है।

जिला उद्योग केन्द्र का अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण होना चाहिए। प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र, इन्टरनेट, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से लैस होना चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत बल की कमी होने के कारण औद्योगिक विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लघु उद्योग समाचार पत्रिका शत-प्रतिशत हिन्दी में भी प्रकाशित हो ताकि कम पढ़े-लिखे लोगों और अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखने वाले भावी उद्यमियों को सोचने और समझने में सुविधा जनक लगे। लघु उद्योग समाचार पत्रिका के हर अंक में लघु उद्योग की स्थापना, संचालन, मशीन का अधिष्ठापन, उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी एक वस्तु के निर्माण हेतु प्रक्रिया को लेकर विशेष आलेख अवश्य ही प्रकाशित हो।

जब मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र के प्रभारी महाप्रबंधक महोदय से उक्त दिलचस्प और महत्वपूर्ण धरातलीय सुझाव और तथ्य प्राप्त हुए तो इन्हें मैं अपनी ओर से अपने कीमती समय देने और अपेक्षित सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया। मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र के प्रभारी महाप्रबंधक महोदय द्वारा दिए गए सुझावों और तथ्यों के आलोक में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। प्रर्याप्त संसाधनों का अभाव, बैंकों द्वारा वित्तपोषण प्रक्रिया में रूकावट आदि कारणों से केन्द्र के पास अपेक्षित इच्छा शक्ति रहने के बावजूद भी भावी उद्यमियों को

यथोचित सहयोग करने की स्थिति नहीं बन पाती है। इसके अलावा बैंकों द्वारा वित्त पोषण इसलिए नहीं हो पाता है- क्योंकि पूर्व में उद्यम लगाने हेतु जिन उद्यमियों ने ऋण लिए हैं- इनके द्वारा समय पर ऋण अदायगी नहीं हो पाती है। बैंक के समक्ष यह एक गंभीर समस्या है। सच्चाई यह होती है कि ऋण लेने के समय उद्यमी जितनी तत्परता दिखाते हैं, बाद में वे उतने ही लापरवाह हो जाते हैं। उनकी मानसिकता बदल जाती है। इसके लिए अपेक्षित है कि सरकार की ओर से अवश्य ही कोई ठोस और कारगर पहल किए जाने चाहिए, ताकि भावी उद्यमियों को निराश नहीं होना पड़े। वे स्वरोजगार-सृजन करके आत्मनिर्भर बन पायें।

मुंगेर की यात्रा समाप्त करके जब मैं वापस हो रहा था तो मुंगेर-जमुई राजपथ में ही एक रेलवे स्टेशन बरियारपुर पड़ता है। यहां कुछ रेलों को छोड़कर करीब-करीब सभी रेलें रूकती हैं। यह रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है। यहां यात्रियों की गहमागहमी बराबर बनी रहती है। यहां भारी संख्या में आस-पास और दूरदराज से लोग आते हैं और अपने गंतव्य तक की यात्रा करते हैं। उक्त राजपथ के दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें कुछ दुकानों में लाय (स्थानीय बोली) जोकि एक प्रकार की खाद्य-वस्तु हैं- यहां बिकती हैं। मैंने सुन रखा था कि- बरियार की लाय बड़ी मशहूर है। एक तो रेलवे स्टेशन होने के नाते, दूसरा मुख्य राजपथ से सटे होने के कारण लाय खरीददारों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। यह एक ऐसी खाद्य वस्तु है जिसमें धान का लावा, गुड़, तिल आदि के प्रयोग किए जाते हैं।

स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से उक्त वस्तुओं का प्रयोग हानिरहित है। चूंकि यहां लाय का उत्पादन होता है और इसकी बिक्री भी होती है, साथ ही यह लघु उद्योग के अर्न्तगत स्थित है तो- मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैं वहां रूक गया। वहां जो मैंने देखा, उसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि- इतनी स्वादिष्ट और शीघ्र ही हजम होने वाली खाद्य वस्तु को ढेर सारी भिनभिनाती हुई मक्खियां प्रदूषित कर रही थीं। लाय पर बैठी हुई ढेर सारी मक्खियों को देखकर किसी का भी मन विरक्त हो सकता है। साथ ही विक्रेताओं की ओर से इन मक्खियों को दूर रखने के लिए कोई तत्परता और सावधानी नहीं दिखाई



पड़ी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वस्तु चाहे कोई भी हो, स्वच्छता और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना एक अनिवार्य शर्त है। उस पर जहां खाद्य वस्तुएं हों तो उसके रखरखाव में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होनी चाहिए तभी उस वस्तु की गुणवत्ता कायम रहेगी।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर जोर-शोर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देने के लिए और इसके सकारात्मक परिणाम आने हेतु कई रचनात्मक योजनाएं बनीं हैं। उसका निष्पादन भी हो रहा है। इसी बिन्दु के आलोक में बरियारपुर के लाय उत्पादन कर्ताओं और विक्रेताओं को चाहिए कि वे स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने हेतु अपनी पूर्ण भागीदारी दें और स्वच्छता भंग करने वाली लाय पर बैठी हुई भिनभिनाती हुई मक्खियों की रोकथाम के लिए कारगर पहल करें। यदि स्वच्छ और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली लाय का उत्पादन होगा तो निश्चित रूपेण इसकी खरीददारी बढ़ेगी, साथ ही उत्पादनकर्ताओं और विक्रेताओं को भारी लाभ भी मिलेगा। लघु उद्योग के तहत् स्वरोजगार सृजन करने का यह सुलभ साधन भी है। बेरोजगारी दूर करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में इसे अपना अपेक्षित है।

वर्तमान में बिहार वासियों के लिए एक सुखद संयोग है कि राज्य सरकार और केन्द्र की शासन व्यवस्था दोनों एक जैसी ह, जो बिहार के शीघ्र विकास के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। बस इसके लिए आवश्यक है, यहां के लोगों में सकारात्मक सोच का विकसित होना। यह तो निश्चित मत है कि जीवन का एक नकारात्मक पहलू है- निट्टलापन और बेरोजगारी। इसका प्रमुख कारण है, आलस्य और जड़ता का होना। अतः अपने नकारात्मक सोच को बदलकर रचनात्मक कदम उठाने का समय आ गया है।

ऐसा देखा गया है कि यहां के लोग जब अपनी सोई ऊर्जा और क्षमता को पहचान लेते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे उल्लेखनीय कार्यों की रूपरेखा बनने लगती है। ऐतिहासिक गरिमा से समृद्ध इस राज्य में कभी 'अंगदेश'

की अपनी विशिष्ट पहचान थी। मुंगेर से लेकर भागलपुर तक के सारे क्षेत्र अंग देश की सीमा में आबद्ध थे। अतीत में यह क्षेत्र सभी दृष्टिकोण से काफी सम्पन्न था। किन्तु वर्तमान में प्राचीन अंगदेश रोजगार के मामले में काफी पिछड़ गया है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अभी भी यह प्राकृतिक संपदाओं से काफी सम्पन्न है। यहां लघु उद्योग के विकास की ढेर सारी संभावनाएं और सुविधाएं मौजूद हैं। आवश्यकता है- शासन-व्यवस्था द्वारा समूचे अंग क्षेत्र का व्यापक पैमाने पर 'रोडमेप' तैयार करवाने की। इस संदर्भ में एक सुखद पहलू यह है कि अभी देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनका नारा है- सपना है- सबका साथ - सबका विकास! यह तभी संभव है जब राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से धरातलीय प्रयास से राज्य के कोने कोने में विकास की किरणों को फैलाने में तत्परता दिखाये। केवल बिहारी ही नहीं, केवल अंग क्षेत्र से ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत के लिए यह स्वर्ण अवसर है कि राष्ट्र की मूल धारा में जुड़कर, सबका विकास-सबका साथ जैसी मानवीय विचारधारा का उद्घोष करते हुए अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का सबक लेकर राष्ट्र को नवप्रगति पथ पर अग्रसर करने का भाव जगाएं और एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, अखंडित भारत के नवनिर्माण की दिशा में संकल्पपूर्वक बढ़ते हुए अपने राष्ट्रीय नागरिक धर्म का निर्वहन करें।

- लेखक का मूल नाम नित्यानंद सिंह है और वे स्वतंत्र पत्रकार तथा सभी चित्रों के छायाकार हैं।



ऐसा रहा एमएसएमई का मेला !

- के. शुभम मिश्रा

प्रगति मैदान प्रदर्शनियों का परिसर है। पूरा परिसर छोटे-छोटे प्रदर्शनी हॉल में विभाजित है। यह परिसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के लिए काफी मशहूर है। इस मेले में भारत के लगभग सभी राज्य, केन्द्रशासित क्षेत्र तथा लगभग सभी मंत्रालय हिस्सा लेते हैं। सभी राज्य अपने राज्यों की प्रगति, संस्कृति, पर्यटन स्थल तथा व्यापार के बारे में जानकारी देते हैं तथा सभी मंत्रालय अपने उद्यमियों और व्यापारियों को प्रोत्साहन देते हैं तथा उसमें लगा हर स्टॉल उस मंत्रालय की उपलब्धियों और उससे जुड़े उत्पादों को दर्शाता है।

सन् 1980 में प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था। तब से अब तक इस व्यापार मेला का आयोजन प्रतिवर्ष 14 नवम्बर से 27 नवम्बर तक किया जाता है। इसी कड़ी में प्रगति मैदान में 37वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। शुरू के कुछ दिन व्यापारियों के लिए तथा बाकी दिन आम लोगों के लिए खुले रहे।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला निर्माताओं, व्यापारियों निर्यातकों और आयातकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। इस मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्द्धन

संगठन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापार संवर्द्धन एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस साल मेले की 'थीम' थी - "स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया"।

प्रगति मैदान प्रदर्शनियों का परिसर है। पूरा परिसर छोटे-छोटे प्रदर्शनी हॉल में विभाजित है। यह परिसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के लिए काफी मशहूर है। इस मेले में भारत के लगभग सभी राज्य, केन्द्रशासित क्षेत्र तथा लगभग सभी मंत्रालय हिस्सा लेते हैं। सभी राज्य अपने राज्यों की प्रगति, संस्कृति, पर्यटन स्थल तथा व्यापार के



जून-नवम्बर, 2017

15





महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय इत्यादि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) में सूक्ष्म यानि घरेलू उत्पाद से लेकर मध्यम यानि बड़े स्तर तक के उत्पाद पर फोकस किया जाता है। इस मंत्रालय के मंडप में स्टॉल लगाने वाले सभी व्यापारी अपने-अपने उत्पाद का प्रदर्शन करते हैं तथा हस्तशिल्प की कला के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं।

व्यापार मेले में फायदा सिर्फ व्यापारी वर्ग का ही नहीं दर्शकों का भी होता है। एमएसएमई मंत्रालय अपने स्टॉल में आए हर दर्शकों को स्वाबलंबी बनने की प्रेरणा देता है- किस प्रकार कम पूंजी से व्यक्ति पूंजीपति बन सकता है, इसकी सीख विभिन्न तरीकों से देता है जिसके फलस्वरूप दर्शकों के मन में भी अपना उद्योग आरंभ कर उद्योगपति बनने की लालसा पैदा होती है।

हमारे समाज की नींव हमारी युवा पीढ़ी है, इसलिए जरूरी है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले और इसी कार्य को व्यापार मेले में एमएसएमई मंत्रालय पन्द्रह दिनों में प्रत्येक जगह लगातार अलग-अलग रोचक ढंग से विभिन्न प्रकार की स्कीम को फिल्मों द्वारा दर्शकों के सामने प्रदर्शित

करता है तथा व्यापार को सफल कैसे बनाया जाए, इसकी सीख देता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

बारे में जानकारी देते हैं तथा सभी मंत्रालय अपने उद्यमियों और व्यापारियों को प्रोत्साहन देते हैं तथा उसमें लगा हर स्टॉल उस मंत्रालय की उपलब्धियों और उससे जुड़े उत्पादों को दर्शाता है। व्यापार मेले में भाग लेने वाले कुछ

लघु उद्योग समाचार



है। यह मंत्रालय आगंतुक दर्शकों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखता है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहती है ताकि किसी भी दर्शक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात दिलाया जा सके। इस मंत्रालय द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के नुस्खे भी सिखाये जाते हैं।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय छोटे से छोटे व्यापारी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनको मौका देता है ताकि वे अपनी कला का प्रदर्शन कर कुछ पूंजी कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के हित में चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देता है। कम समय में किसान किस प्रकार के पैदावार को लगाएं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो - यह जानकारी भी विभिन्न माध्यमों से वह देता है जिनमें नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा विभिन्न प्रकार की लोकोक्ति द्वारा लोगों को कृषि करने तथा पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जाता है, जिसकी एक झलक है :-

जून-नवम्बर, 2017

“एक पुत्र सौ पुत्र के समान है” तथा “ पेड़ लगाओ, धरती को मृत होने से बचाओ।”

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय व्यापार मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर 70% जल है परंतु यह कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है और निरंतर पीने योग्य जल की मात्रा बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। कम होने से तात्पर्य जल का खत्म होना नहीं, दूषित होना है। इस मंत्रालय द्वारा किस प्रकार दूषित जल को पीने योग्य बनाया जा सके तथा नष्ट हो रहे जल को बचाया जा सके, को विभिन्न नुक्कड़ नाटकों के मंचन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

यह मेला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि पा रहा है, जिसके कारण देश-विदेश के कोने-कोने से लोग इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। विश्व की लगभग सभी प्रमुख कंपनियां अपने उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए इस अवसर का हर वर्ष प्रतीक्षा करती हैं। यह मेला देश के गौरव का प्रतीक बन गया है।

मुझे पिछले तीन वर्षों से इस व्यापार मेले को देखने

17



मेले में देश के सभी प्रदेशों की प्रगति की झाकियां देखने को मिलती है। अलग-अलग राज्यों के पैवेलियन में उस प्रदेश की कला-संस्कृति और विकास की झाकियां देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रादेशिक झाकियों के अतिरिक्त सेना, तकनीक एवं संचार के क्षेत्र में देश की प्रगति के नमूने बड़े ही आकर्षक ढंग से दर्शाए जाते हैं।

का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। इस मेले के अंदर प्रवेश करने पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हमारे सामान आदि की जांच के बाद ही हमें अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। मेले में काफी चहल-पहल दिखाई पड़ती है तथा सभी लोग उत्साह एवं उत्सुकता से भरे नजर आते हैं। बच्चे तथा युवाओं में मेले का उत्साह देखते ही बनता है।

मेले में देश के सभी प्रदेशों की प्रगति की झाकियां देखने को मिलती है। अलग-अलग राज्यों के पैवेलियन में उस प्रदेश की कला-संस्कृति और विकास की झाकियां देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रादेशिक झाकियों के अतिरिक्त सेना, तकनीक एवं संचार के क्षेत्र में देश की प्रगति के नमूने बड़े ही आकर्षक ढंग से दर्शाए जाते हैं।

इस मेले में विदेशी कंपनियों के अतिरिक्त हमारे देश की प्रमुख कंपनियां तथा स्वदेशी वस्तुओं को देखने का मौका मिलता है।

इस मेले की रौनक खादी वस्त्र और वस्तुओं से और भी बढ़ जाती है। ग्रामोद्योग का सामाजिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक उद्देश्य, बेचने योग्य सामग्री प्रदान कराना और योग्य सामग्री प्रदान कराना और व्यापक उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण कराने के उद्देश्य की पूर्ति व्यापार मेले में नजर आती है। खादी वस्त्र नहीं एक नवविचार है जो नई पीढ़ी को रोजगार देने और गांधी जी की स्वदेशी अपनाने की आवाज को बुलंद करती हैं।





आज भारत में व्यापार मेले द्वारा “खादी अपनाओ देश बढ़ाओ” का संदेश प्रसारित होते नजर आता है। खादी हमारे देश की ताकत है और यही हमारी पहचान है। आज खादी के पास अनेक उतपाद उपलब्ध हैं, जिसमें किसी अंग्रेज की मेहनत नहीं बल्कि भारतीयों की मेहनत और लगन दिखाई देती हैं। व्यापार मेले में गांधी जी का चरखा आकर्षण का केन्द्र बना रहता है और सूत कातने की कला प्रशिक्षकों द्वारा दिखाई जाती है। इस प्रशिक्षण में कई दर्शक हिस्सा लेते हैं तथा सूत कातने की विधि भी सीखते हैं। व्यापार मेले में खादी पैवेलियन लोगों को बहुत आकर्षित करता है। जिसका मुख्य कारण खादी के फैशनेबल ड्रेस होते हैं। इसके अलावा किस्म-किस्म के अचार, पापड़, सौंदर्य वस्तुएं, गृह-सज्जा की वस्तुएं आदि दर्शकों को स्वदेशी वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं।

कॉयर उत्पाद से निर्मित वस्तुएं भी मेले में दर्शकों का मन मोह लेती हैं। ये सारी वस्तुएं नारियल के रेशे से बनी होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हैं - छाता, बैग, चटाई, पायदान, गृह-सज्जा की वस्तुएं आदि। इसका श्रेय केरल और तमिलनाडु को जाता है, जहां ऐसे कारखाने स्थापित

किए गए हैं जो कॉयर उत्पाद से नवपीढी को रूबरू कराते हैं। दर्शक बड़ी संख्या में कॉयर उत्पाद को खरीदते हैं।

इस मेले की खासियत यह है कि इसमें एक ही जगह पर सभी राज्यों और सभी संघ शासित क्षेत्रों के उत्पाद और खान-पान से जुड़े व्यंजन देखे जा सकते हैं, उनका स्वाद चखा जा सकता है और एक ही साथ दुनिया के कई देशों के भी उत्पाद यहां पर देखे जा सकते हैं।

व्यापार मेले में अलग फूड स्टॉल से ज्यादा प्रसिद्ध विभिन्न राज्यों के फूड स्टॉल होते हैं। इनकी प्रसिद्धि के कारण हर राज्य का खास व्यंजन होता है, जिसमें बिहार का लिट्टी-चोखा, लीची का फ्रेश जूस, शुद्ध गुड़ और घी से निर्मित ठेकुआ, पंजाब की लस्सी और मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, आंध्र का इडली सांभर तथा डोसा, गुजरात का खम्मड़, ढोकला-हांडवा, खारवड़ा, महाराष्ट्र का बड़ा पाव आदि व्यंजन दर्शकों को अपनी तरफ खींचते हैं तथा विभिन्न राज्यों के अलग-अलग पोशाक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। साथ ही भिन्न-भिन्न राज्यों के हस्तशिल्प लोगों का मन मोह लेते हैं। इसके अलावा दर्शकों के मनोरंजन के लिए लोक नृत्य,



लोक गायन का आयोजन किया जाता है। 'सेल्फी' लेने के लिए भी 'सेल्फी पाइंट' बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जवानों द्वारा किया गया विशेष आयोजन भी सराहनीय होता है, जिसमें उनका पोशाक, गोली-बंदूक देखने की लालसा दर्शकों के मन में दिखाई पड़ती है। इसमें देश की सुरक्षा के बारे में बताया जाता है।

व्यापार मेले की भीड़ को ध्यान में रखते हुए एटीएम, शौचालय और शॉटल बस की व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा जाता है। बच्चों के गुम होने पर माइक द्वारा सूचना देना तथा सामान खोने पर लोगों को सूचित करना तथा अन्य जानकारियां लाउड स्पीकर द्वारा दिया जाना महत्वपूर्ण है। इस मेले में कलाकार बुलाए जाते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लेते हैं।

इस बार 37वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एमएसएमई के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। देश के हरेक कोने से आए व्यापारी प्रफुल्लित होकर अपने घर लौटे और इस बार उनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ा। मेले में एमएसएमई का प्रभाव हर राज्य के पैवेलियन में देखने को मिला। इस मेले में महिला उद्यमी भी अपने उद्योग

द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करती नजर आ रही थीं। इस प्रकार यह मेला नवयुवकों को स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का संदेश देता नजर आया। मेले में एमएसएमई एक्सपो-2017 का आयोजन भी महत्वपूर्ण रहा।

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह ने प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई एक्सपो 2017 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुणवत्ता विनिर्माण और एमएसएमई का समग्र विकास देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माण के क्षेत्र के प्रमुख हिस्से हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारत को स्टार्ट-अप केन्द्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सपो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए उद्यमों के लिए एक बहुत अच्छा मंच है।

एमएसएमई एक्सपो - 2017 का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया गया। व्यापार मेले के दौरान 50 से अधिक उद्यम अपने

उत्पादों का इसमें प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। इसमें जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना, एससी/एसटी केन्द्र और राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल थे। प्रतिभागियों में महिला उद्यमी, पूर्वोत्तर राज्यों और अल्पसंख्यकों के साथ-साथ एससी/एसटी एवं अन्य उद्यमी जैसे विविध वर्ग शामिल थे। यह आयोजन स्थायी व्यापार गठजोड़ बनाने के लिए भी अवसर प्रदान करता है। इंजीनियरिंग खाद्य, रसायन, सौंदर्य प्रसाधन, हस्तशिल्प, वस्त्र एवं हौजरी, विद्युत उपकरण, ऑटो उपकरण, रेडिमेड गारमेंट्स, खान और आभूषण तथा अन्य उत्पादों का एमएसएमई एक्सपो-2017 में प्रदर्शन किया गया है।

एमएसएमई एक्सपो-2017 के उद्घाटन के दौरान एमएसएमई सचिव डॉ. ए.के. पंडा और अपर सचिव एवं डीसी (एमएसएमई) श्री राम मोहन मिश्रा भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने 'मेक इन इंडिया'

अभियान के मुख्य विन्दुओं, सहजता से व्यापार करने, सार्वजनिक - निजी भागीदारी व मांग के सामर्थ्य का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धांततः भारत का विकास 'सामूहिक जिम्मेदारी है और उत्पादन क्षेत्र की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए - खासतौर से निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा अपने देश को विकसित करने के लिए उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद प्रत्यक्ष विदेश निवेश के अवसर की सहायता से राष्ट्र की बेहतरी का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत को प्रतिযোগी लाभ मिल रहा है। भारत के घरेलू बाजार में करीब 600 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता शामिल हैं, भारत के कामगारों की मेहनताना भी प्रतिस्पर्धी है, यहां प्रतिभाओं की बड़ी खेप है, जिसमें सबल इंजीनियरिंग परितंत्र भी शामिल हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर यह भी बताया कि सरकार की नई उत्पादन नीति में जीडीपी में उत्पादन के





हिस्से को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और दीर्घकालिक आधार पर 100 मिलियन रोजगार पैदा करने का जरिया शामिल है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मुख्य नीति साधनों में राष्ट्रीय निवेश व उत्पादन क्षेत्र (एनआईएमजी) की स्थापना करना, जहां कि औद्योगिक टाउनशिप के लिए स्व-प्रशासित स्वायत्त समूह होगा, उत्पादन क्षेत्र में लघु मध्यम उद्यम के लिए आसान वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह ने प्रगति मैदान में कॅयर बोर्ड पैवेलियन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारतीय कॅयर उद्योग पहले केरल तक सीमित था किन्तु अब यह पूर्वोत्तर राज्यों सहित 22 से अधिक राज्यों में फैल गया है। कॅयर बोर्ड की ओर से कॅयर इकाइयां स्थापित करने और उद्यमिता विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने

कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 12वीं योजना अवधि के दौरान 4000 से भी अधिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। श्री सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कॅयर उद्योग देश के आर्थिक विकास और युवाओं को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने खादी को अपनाने पर भी बल दिया।

इस तरह प्रगति मैदान में अपेक्षाकृत लघु स्तर पर लगा मेला इस बार भी लघु उद्योगों के लिए वरदान साबित हुआ।

- लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं और इस लेख में प्रकाशित सभी चित्रों की छायाकार भी हैं।

भ्रष्टाचार : समस्या एवं निवारण

- अनिल कुमार

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। जिसमें मनुष्य भ्रष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित होता है अथवा उसे प्रोत्साहित करता है।

जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत जैसे महान देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। आज भारत में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार को दर्शाते हैं। भ्रष्टाचार में कई रंगरूप हैं जैसे रिश्वत, काला बाजारी, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर मंहगा बेचना आदि।

भ्रष्टाचार के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :-

असंतोष - कभी कभी मनुष्य जो कुछ भी कमाता है वह उससे सन्तुष्ट नहीं होता है। अतः और ज्यादा कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लेता है।

स्वार्थ और असमानता - आर्थिक, समाजिक, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आपको भ्रष्ट बना देता है।

हीनता और ईर्ष्या की भावना - हीनता और ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त व्यक्ति भी भ्रष्टाचार का रास्ता अपना लेता है। साथ ही रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद की भावना भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं।

क्षेत्रीयता एवं जातिवाद की भावना - क्षेत्रीयता एवं जातिवाद की भावना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

अतः भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है। आज भारत देश में भ्रष्टाचार की जड़ें तेजी से फैल रही हैं यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। भ्रष्टाचार को प्रभाव अत्यन्त खतरनाक है।

भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम:-

- भ्रष्टाचार के कारण समाज में असन्तोष फैलता है।
- भ्रष्टाचार के कारण दैनिक इस्तेमाल का सामान मंहगा हो जाता है।
- भ्रष्टाचार के कारण अच्छे विद्यार्थी का दाखिला अच्छे स्कूल या कालेज में नहीं हो पाता है।
- भ्रष्टाचार के कारण योग्य व्यक्ति नौकरी पाने से वंचित रह जाता है।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय:-

- समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार नामक रोग को मिलजुल कर मिटाना होगा। हमें विद्यालय स्तर से ही बच्चों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना होगा और इसके दुष्परिणाम से अवगत कराना होगा। सरकार को इस दिशा में कड़े कानून बनाने होंगे और सख्ती से अमल में लाना होगा।
- भ्रष्टाचार रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए।
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना हेतु अखबार में विज्ञापन देने चाहिए।
- प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता को सख्ती से लागू करना चाहिए।

इन उपायों को अपनाकर हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। अतः इस प्रकार हम एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकते हैं

- लेखक विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में सहायक निदेशक (सतर्कता) हैं।



राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह-2015

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 27 जून, 2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह-2015 आयोजित किया। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस घोषित किया है, इसे ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को, सरकार की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए इस दिन का चयन किया है। इस अवसर तत्कालीन पर माननीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र, माननीय एमएसएमई राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह और हरिभाई पारथीभाई चौधरी, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, कॅयर बोर्ड के अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन उपस्थित थे।

तत्कालीन केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एमएसएमई के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। कृषि के बाद खादी व ग्रामोद्योग और कॅयर क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। हाल के वर्षों में एमएसएमई ने 10 प्रतिशत से अधिक का विकास दर दर्शाया है, जो कि बड़े कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा दर्ज विकास दर से कहीं अधिक है। एमएसएमई 50 मिलियन से अधिक उद्यमों के माध्यम से 110 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जो छह हजार से अधिक उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता को देखते हुए एमएसएमई क्षेत्र हमेशा से वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकता में रहा है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में मंत्रालय की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिए जाने वाले ऋणों के कवरेज को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रु. कर दिया

गया है और साथ ही क्रेडिट गारंटी फंड के कॉर्पस को भी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोलेट्रल मुक्त ऋण मुहैया कराने के लिए 2500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7500 करोड़ रु. कर दिया गया है।

केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने उपस्थित समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एमएसएमई मंत्रालय ने “व्यवसाय करने को आसान बनाने” और “डिजिटल इंडिया मिशन” के लिए कई कदम उठाए हैं। सितम्बर, 2015 में लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल उद्योग आधार ज्ञापन जो आधार के साथ संबद्ध है को बिना किसी शुल्क और स्व-प्रमाणन आधार पर कुछेक मिनटों में ही फाइल किया जा सकता है। इसके साथ ही एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं की सूचना सिंगल विंडो My MSME Mobile App पर प्राप्त कर सकता है।

उत्कृष्ट उद्यमिता क्षमता, उत्कृष्ट उत्पाद गुणवत्ता, निर्यात में उत्कृष्टता, नव-प्रवर्तन एवं लीन विनिर्माण तकनीक में उत्कृष्टता के रूप में एमएसएमई क्षेत्र में सफल उद्यमियों की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। पुरस्कार स्वरूप प्रथम, द्वितीय और तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रत्येक श्रेणी में 1,00,000/- रु., प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी दिए जाते हैं। एक उत्कृष्ट महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक उत्कृष्ट उद्यमी और पूर्वोत्तर क्षेत्र से एक उद्यमी और एक सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग उद्यमी को सम्मान स्वरूप विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल उद्यमियों द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देना है बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों सहित देश के व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है।

बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने में उनके उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए

लघु उद्योग समाचार



बैंकों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं। एमएसई को ऋण मुहैया कराने में उत्कृष्टता और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने में उत्कृष्टता की इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक में तीन-तीन राष्ट्रीय पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और एक विशेष पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंकों में से एक को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रमाण-पत्र के साथ ट्रॉफी के रूप में दिए जाते हैं।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए तत्कालीन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र जी ने सूचित किया कि वर्ष 2015 के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या 56 है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 50 और बैंकों की संख्या 6 है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि एमएसएमई मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के “डिजिटल इंडिया” और “मेक इन इंडिया” के विजन के अनुरूप इस दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुरस्कार विजेताओं को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि एमएसएमई क्षेत्र के अन्य उद्यमी भी पुरस्कार विजेताओं द्वारा स्थापित उदाहरणों का अनुसरण करेंगे। उन्होंने माननीय

प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए एमएसएमई क्षेत्र से जेड और लीन विनिर्माण के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने “डिजिटल एमएसएमई स्कीम” लॉन्च की और एसएपी इंडिया, इंटेल और एचएमटी के साथ सम्पन्न तीन समझौता ज्ञापन सौंपे। इन कदमों से मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता के लिए किए गए प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा। डिजिटल एमएसएमई योजना क्लाउड कम्प्यूटिंग के इर्द-गिर्द घूमती है जो एमएसएमई द्वारा स्थापित इन-हाउस आईटी अवसंरचना की तुलना में लागत प्रभावी और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रहा है। क्लाउड कम्प्यूटिंग में एमएसएमई व्यवसाय संबंधी अपनी प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए सामान्य के साथ-साथ विशेष रूप से निर्मित आईटी अवसंरचना जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निवेश के बोझ से क्लाउड कम्प्यूटिंग मुक्त है। इसलिए कैपेक्स ओपेक्स में रूपांतरित होता है। यह योजना इस नए दृष्टिकोण अर्थात् आईसीटी के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग की दिशा में एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगा। ■

जीएसटी से कर बोझ में कमी

मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय ने 13 जुलाई 2017 को फिक्की के साथ मिलकर ‘जीएसटी’ और ‘डिजिटल एमएसएमई’ विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। तत्कालीन केन्द्रीय मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि मंत्रालय पूरे देश में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि वे उद्यमियों के ऋण संबंधी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें।

मंत्री महोदय ने आगे कहा कि जीएसटी से कर बोझ में महत्वपूर्ण कमी आएगी और यह औपचारिक अर्थव्यवस्था

के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार विकास दर में बढ़ोत्तरी होगी और रोजगार सृजन के अवसर बनेंगे। इसलिए मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम को जीएसटी को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। श्री मिश्र ने बताया कि मंत्रालय ने जीएसटी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) के मुख्य कार्यालय में जीएसटी कक्ष बनाए गए हैं। एनएसआईसी ने टोल फ्री नं. 1800-111-955 के साथ एक सुविधा केन्द्र भी बनाया है। अब तक एमएसएमई के प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्र अधिकारियों ने लगभग 12000 उद्यमियों को जीएसटी विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

श्री मिश्र ने कहा कि उन्होंने स्वयं ही पूर्वोत्तर के



गुवाहाटी और अगरतला में जीएसटी पर जानकारी दी है। मंत्री महोदय ने सभी अधिकारियों को जीएसटी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्वीटर के उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से जीएसटी के संबंध में जानकारी देने व अधिसूचना प्रकाशित करने को कहा है। इसके अलावा अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के 200 अधिकारी जिलास्तर पर जीएसटी के लागू होने की निगरानी करेंगे। मंत्रालय के दो संयुक्त सचिवों को यह कार्यभार दिया गया है।

श्री मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय की पत्रिका 'लघु उद्योग समाचार' ने जीएसटी पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया है। मंत्रालय के सचिव को कैबिनेट सचिव स्तरीय समीक्षा समिति में शामिल किया गया है। जीएसटी के साथ ही मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं को लागू करने संबंधी दिशा-निर्देशों का सरलीकरण किया है। पीएमईजीपी को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस तथा आईजीएमएस) स्थापित की गई है। ई-कार्यालय और मोबाइल अनुकूल वेबसाइट प्रारंभ किए गए हैं। माई-एमएसएमई मोबाइल एप, एमएसएमई डाटा बैंक पोर्टल और डिजिटल एमएसएमई पोर्टल भी शुरू किए गए हैं।

मंत्री महोदय ने जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल एमएसएमई एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है। यह नया दृष्टिकोण है, उत्पादन और व्यापार प्रक्रिया के लिए आईसीटी के सहारे क्लाउड कम्प्यूटिंग ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उत्कृष्टता हासिल की जा सके। राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण असंगठित उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। राज्यमंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई ने कहा कि एक बहुत बड़ी समानांतर अर्थव्यवस्था जो अब तक विद्यमान है, वह जीएसटी के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगी। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि इनपुट टैक्स का फायदा लेने के लिए वे अपने व्यापारियों का चुनाव सोच समझ कर करें। एमएसएमई के सचिव श्री अरूण कुमार पांडा ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जीएसटी के अन्तर्गत एमएसएमई क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर विशेष जानकारी प्रदान की। उन्होंने डिजिटल एमएसएमई जैसे आईसीटी जैसी योजनाओं का उपयोग करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में सीबीईसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने एमएसएमई उद्यमियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। ■

भुगतान पोर्टल- एमएसएमई समाधान का उद्घाटन

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विलंब भुगतान पोर्टल- एमएसएमई समाधान का उद्घाटन किया। इस पोर्टल से देश भर के छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर ये उद्यमी केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से अपने भुगतान में देरी के मामलों को दर्ज करा सकेंगे। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री अरूण कुमार पांडा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और

मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के भुगतान में देरी से जुड़े मामलों से निपटने के प्रावधान हैं। प्रावधानों के अनुसार किसी भी वस्तु या सेवा को स्वीकार करने के 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर आपूर्तिकर्ता को खरीददार, बैंकों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से तीन गुना अधिक ब्याज के साथ भुगतान करेगा।

इस पोर्टल के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी अपने मामले की प्रगति रिपोर्ट को भी देख सकेंगे। ■

लघु उद्योग समाचार



राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मेलन का उद्घाटन

एससी एवं एसटी उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए तीन सेक्टर कौशल परिषदों के साथ एमओयू

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा आयोजित किये गये राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के लिए प्रथम रेडियो जिंगल भी जारी किया। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में एससी (अनुसूचित जाति) एवं एसटी (अनुसूचित जनजाति) उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित परितंत्र को मजबूत करने हेतु सामूहिक एवं समन्वित कदम उठाने की जरूरत है। श्री नायडू दिल्ली में केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी-एसटी हब सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब समाज के वंचित एवं अल्प सुविधा प्राप्त तबकों का उन्नयन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास के लिए हमें एकीकृत एवं बहुआयामी विकास एजेंडे की जरूरत है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना अत्यंत जरूरी है और इससे बेरोजगारी की समस्या सुलझेगी तथा आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए उद्योग एवं कृषि

दो महत्वपूर्ण कारक हैं।

उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टैंड-अप, स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन तथा नवाचार का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें नई गति प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया, कौशल भारत, डिजिटल इंडिया एवं स्वच्छ भारत जैसे सभी कार्यक्रमों को प्रत्येक तबके तक पहुंचना चाहिए तथा प्रत्येक को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है, ऋणों की उपलब्धता अहम है और तकनीकी उन्नयन भी महत्वपूर्ण है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की चार दीवारी है तथा कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोजक है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी यह क्षेत्र अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर मेक इन इंडिया के जरिए विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022 तक बढ़कर जीडीपी का 25 प्रतिशत हो जाने की परिकल्पना की गई है, वहीं दूसरी ओर इस लक्ष्य की प्राप्ति में एमएसएमई क्षेत्र से अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाएगी।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कौशल उन्नयन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि एससी/एसटी उद्यमियों का समग्र विकास संभव हो सके। उन्होंने 2000 से ज्यादा उद्यमियों का कौशल बढ़ाने हेतु सेक्टर कौशल परिषदों के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रीय एससी/एसटी हब का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के उद्देश्यों को समर्थन देने में संगठनों और इन्क्यूबेटरों



को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संगठन को अपने-अपने क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और उद्यमियों का मार्ग दर्शन करने के लिए निश्चित तौर पर आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' समावेशिता के विचार की उत्पत्ति है। उन्होंने एससी-एसटी समुदाय के बीच उद्यमिता सुनिश्चित करने के लिए अपने मंत्रालय की ओर से एमएसएमई मंत्रालय को पूर्ण सहयोग देने का भी वादा किया।

जनजातीय कार्य मंत्री जुआल ओराम ने कहा कि वह इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि सरकार ने देश के एसटी समुदाय के उन्नयन के लिए एनएसएसएच जैसी अनोखी पहल की है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सभी एमएसएमई को बड़े उद्यमों से प्रतिस्पर्धा के कारण अपने उत्पादों के विपणन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि सार्वजनिक खरीद नीति एक स्वागत योग्य कदम है।

एमएसएमई मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद कहा और इस बात का उल्लेख किया कि यदि एससी-एसटी उद्यमियों को 5,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल सकें तो यह इस तरह के उद्यमियों के लिए काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जिस दिन रोजगार मांगने वाले रोजगार देने लगेंगे, उस दिन प्रत्येक व्यक्ति का सपना साकार हो जाएगा।

एमएसएमई मंत्रालय में सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कार्यक्रम संपर्क सुनिश्चित करने और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को कनेक्ट करने तथा हर व्यक्ति को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने का माध्यम है। संयुक्त सचिव, एसएमई ने हब द्वारा की गई पहलों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी और इसके साथ ही अब तक हुई प्रगति पर रोशनी डाली।

इस सम्मेलन से उद्योग संगठनों एवं इन्क्यूबेटर्स की विभिन्न अंतर्दृष्टि सामने आई जिससे सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश को साकार करने के मार्ग में मौजूद कमी को समझने में मदद मिली। इस सम्मेलन के दौरान एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के समग्र विकास के लिए अभिनव रणनीतियां पेश की गईं। इस दौरान आयोजित परिचर्चा अत्यंत सार्थक साबित हुई। इससे राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के उद्देश्यों की पूर्ति में काफी मदद मिली।

150 से भी अधिक उद्योग संगठनों और इन्क्यूबेटर्स के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया जिसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व रहा। इस दौरान एनएसएसएच के साथ सहयोग करने और वर्तमान एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान बाजार पहुंच, क्षमता निर्माण, चुनौतियों का सामना करने, तकनीकी उन्नयन इत्यादि से संबंधित अनेक अभिनव सुझाव दिये गये। इस सत्र के दौरान हब के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक हितधारक द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका के साथ-साथ भावी कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके अलावा, 'एनएसएसएच' की क्षमता निर्माण पहलों के तहत एससी-एसटी उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीन सेक्टर कौशल परिषदों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।



प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का मूल्यांकन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह को गुरुग्राम स्थित प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पर किया गया मूल्यांकन अध्ययन पेश किया गया। इस संस्थान को जनवरी, 2017 में पीएमईजीपी का मूल्यांकन अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इस अध्ययन का उद्देश्य रोजगार सृजन और ग्रामीण एवं शहरी कारीगरों तथा बेरोजगार युवाओं की आमदनी में वृद्धि के लिहाज से इस योजना के असर, स्कीम के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर गौर करना तथा इन्हें सुलझाने के तरीके बताना एवं इस योजना में और सुधार करने के लिए आवश्यक सिफारिशें पेश करना था।

नमूने के आकार का चयन स्तरीकृत क्रम रहित नमूनाकरण आधार पर किया गया था। वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2015-16 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 2,00,885 सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की गई। इन इकाइयों पर विचार किया गया, जिनमें से 5 फीसदी नमूना कवरेज अर्थात लगभग 10,108 इकाइयों को क्रम रहित आधार पर 30:30:40 के अनुपात में तीन क्रियान्वयनकारी एजेंसियों अर्थात केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी के बीच सूचीबद्ध करने की मांग की गई।

अध्ययन के मुख्य अवलोकन

- * यह योजना टिकाऊ रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम रही है। इस योजना के तहत स्थापित की गई इकाइयों ने पूरे साल के साथ-साथ कई वर्षों के लिए रोजगार मुहैया कराए।
- * इस योजना की पहुंच काफी अच्छी है। इसने समाज के लगभग सभी तबकों (सामाजिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, स्थान इत्यादि के आधार पर) को लक्षित किया है।

- * प्रति परियोजना औसत रोजगार - 7.62
- * इकाई रोजगार सृजित करने की औसत लागत - 96,209 रुपये
- * इकाई रोजगार सृजित करने की अधिकतम लागत - 2,75,621 रुपये (नगालैंड)
- * इकाई रोजगार सृजित करने की न्यूनतम लागत - 64,735 रुपये (तमिलनाडु)
- * प्रति परियोजना औसत लागत - 7,33,423 रुपये

समस्या वाले क्षेत्र :

- * विभिन्न चरणों में ऋण मंजूरी की प्रक्रिया में देरी
- * रेहननामा और जमानत की मांग करना
- * भौतिक सत्यापन और मार्जिन मनी के समायोजन में देरी
- * कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग, मार्गदर्शन करना, डेटा तक पहुंच और जानकारी देना या रिपोर्टिंग
- * उत्पादों का विपणन

प्रमुख सिफारिशें :

1. क्षेत्रीय अधिकारियों (ये लाभार्थी एवं एजेंसियों के बीच प्रमुख संपर्क हैं और वर्तमान में अपर्याप्त हैं) की उपलब्धता बढ़ाना।
2. ईडीपी प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री को और ज्यादा प्रासंगिक तथा कठोर बनाने की जरूरत है। ऑनलाइन ईडीपी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
3. मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित तकनीकी एवं प्रबंधकीय



संस्थानों (जैसे कि आईआईटी और आईआईएम) के एमओओसी (व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम) के साथ सामग्री (कंटेंट) साझेदारी/एकीकरण

4. लाभार्थियों का आगे भी मार्गदर्शन करने के लिए एजेंसियां प्रमुख प्रबंधन संस्थानों (भारत/विदेशी) से प्रशिक्षुओं की भर्ती करने पर विचार कर सकती हैं।
5. प्रशिक्षु की पहचान के सत्यापन एवं प्रगति के लिए 'आधार' के साथ एकीकरण।
6. ऋणों की अदायगी के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करना- ऐसे लोग जिनकी मार्जिन मनी को

सफलतापूर्वक समायोजित कर दिया गया है उन्हें सब्सिडी प्राप्त ऋणों (जैसे कि 15 फीसदी सब्सिडी) के दूसरे दौर के विकल्प के साथ पुरस्कृत करने की जरूरत है।

7. ऋण आवेदन से जुड़ा निर्णय (स्वीकृत अथवा नामंजूर करना) लेने के लिए बैंकों पर समयसीमा (या तो 60 दिन या 90 दिन) लागू करना।
8. ऋण के नकद ऋण खाता (सीसीए) घटक को कम किया जा सकता है। अधिकतम सीसीए कुल ऋण का 40 फीसदी तक हो सकता है।

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब सम्मेलन में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा

राष्ट्रीय एससी एसटी हब सम्मेलन की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार पांडा ने की। मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 20 मंत्रालयों के लगभग 50 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में बातचीत का उद्देश्य सभी विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को एक साथ लाना और सार्वजनिक खरीददारी नीति के जनादेश को प्राप्त करने में अंतर और चुनौतियों को समझने के लिए विचार विमर्श शुरू करना है। इस बातचीत का उद्देश्य पूरे एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र पर निरंतर और अपेक्षित प्रभाव डालने के लिए रणनीति तैयार करने का अनुमान लगाना है। 20 मंत्रालयों की 50 से अधिक सीपीएसई की भागीदारी से इस सम्मेलन का उद्देश्य सीपीएसई की खरीद आवश्यकताओं के लिए समझ को विकसित करना और उन्हें एससी/एसटी उद्यमियों को गति प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करके विक्रेता विकास कार्यक्रम में मदद प्रदान करना है।

एमएसएमई मंत्रालय, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के माध्यम से, लगातार इन उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए कार्य कर रहा है और इसने अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं। इस सम्मेलन में सभी चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और निकट भविष्य में योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा।

एससी एसटी उद्यमियों से सामानों और सेवाओं की खरीद के बारे में सीपीएसई के सामने आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। सीपीएसईएस से सूचनाओं और सुझावों को प्राप्त करने के लिए इस सम्मेलन के दौरान एक खुली चर्चा का आयोजन किया गया था। विचार विमर्श में मुख्य रूप से इन विषयों पर प्रकाश डाला गया:

1. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई (एससी/एसटी एमएसई सहित) से सीपीएसई द्वारा की गई खरीददारी की वर्तमान स्थिति
2. एससी/एसटी विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जा



रहे उत्पादों और सेवाओं के विवरण सहित उनके समेकित डेटाबेस की आवश्यकता

3. एससी/एसटी एमएसई के कौशल अंतर से निपटने के लिए विशेष रूप से विक्रेता विकास कार्यक्रम को आयोजित करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना
4. सूचनाओं के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इस सम्मेलन में सार्वजनिक खरीद नीति के जनादेश को प्राप्त करने के अंतराल को समझने में सीपीएसई से विभिन्न निरीक्षण सामने आये और एससी/एसटी उद्यमियों के एमएसई के समग्र विकास के लिए नवाचारी रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। चर्चा बहुत उपयोगी रही जो राष्ट्रीय एससी एसटी हब

के उद्देश्यों को पूरा करने में काफी मददगार होगी।
पृष्ठभूमि: माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये किये राष्ट्रीय एससी-एसटी हब का उद्देश्य, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण में सहायता करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है ताकि उन्हें सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद नीति 2012 तैयार की है जिसमें यह प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा माल और सेवाओं की कुल खरीद का 20% एमएसई से किया जाएगा और ऐसी खरीदारी (कुल खरीद का 4%) की 20% खरीदारी एससी और एसटी स्वामित्व वाली एमएसई से की जाएगी। ■





केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए किये गये ताजा प्रयासों के महत्वपूर्ण दृश्य:



जून-नवम्बर, 2017

33







June-November, 2017

35



Marketing Promotion – A need for MSME Sector

- S.R. Samuel and A.K. Verma

Fast changing global economic scenario has thrown up various opportunities and challenges to the MSMEs in India. While on the one hand, many opportunities are opened up for this sector to enhance productivity and look for new markets at national and international levels, it has also, on the other hand, put an obligation to upgrade their competencies to meet the competition as new products which are launched at an astonishing pace and are available worldwide in short time. Micro, Small & Medium Enterprises do not have any strategic tools / means for their business / market development as available with large industries. In the present competitive age, Marketing is one of the weakest areas wherein MSMEs face major problems.

Background

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last five decades. MSMEs not only play crucial role in providing large employment opportunities at comparatively lower capital cost than large industries but also help in industrialisation of rural & backward areas, thereby, reducing regional imbalances, assuring more equitable distribution of national income and wealth. MSMEs are complementary to large industries as ancillary units and contribute enormously to the socio-economic development of the country.

Fast changing global economic scenario has thrown up various opportunities and challenges to the MSMEs in India. While on the one hand, many opportunities are opened up for this sector to enhance productivity and look for new markets at national and international levels, it has also, on the other hand, put an obligation to upgrade their competencies to meet the competition as new products which are launched at an astonishing pace and are available worldwide in short time. Micro, Small & Medium Enterprises do not have

any strategic tools / means for their business / market development as available with large industries. In the present competitive age, Marketing is one of the weakest areas wherein MSMEs face major problems.

Marketing, a strategic tool for business development, is critical for the growth and survival of MSMEs. Due to the lack of information, scarcity of resources and unorganized ways of selling / marketing, MSME sector often faces problems in exploring new markets and retaining existing ones. Such asymmetries in information, being not aware of the new market where they may sell their products and buyer also having lack of knowledge about the products manufactured by MSMEs result in severe impediments to the growth and survival of MSMEs in a highly competitive environment. MSMEs do not have sufficient resources at their command and, therefore, need institutional support for marketing their products at national and international level.

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing various policies / schemes / Programmes to provide assistance to improve their competitiveness and international market exposure to MSME Sector enabling them to



The scheme Marketing Assistance & Technology Upgradation (MATU) is playing a vital role in facilitating the marketing avenues to MSMEs in national and international markets.

tap and develop domestic / overseas markets. Some of such policies / scheme include encouraging Micro and Small Enterprises (MSEs) for adoption of Bar coding on products and its certification by recognised national / International Bodies for increase in marketability of products in national / international Market, creating consciousness and to educate the MSMEs about importance of packaging in marketing, acquaint them with latest packaging technology, import export procedure latest development in international trade etc. by organising International & National Workshops / Seminars on marketing / packaging/ topics relevant to MSME sector, encouraging MSME units to participate in Domestic / International Trade Fairs etc. The scheme Marketing Assistance & Technology Upgradation (MATU) is playing a vital role in facilitating the marketing avenues to MSMEs in national and international markets. The brief of scheme is as follows:

- 1. Objective:** To encourage manufacturing Micro and Small Enterprises (MSEs) in tapping and developing domestic / overseas markets, popularising adoption of Bar Coding of products, facilitate marketing linkages and educate on relevant topics of marketing by organising International & National Workshop/ Seminar.
- 2. Eligibility criteria:** Micro/Small Enterprise should have EM part II/ Udyog Aadhar Memorandum.
- 3. Domestic Trade Fairs / Exhibitions:** The Financial assistance of 80% of space rent paid for General category units and 100% for SC/ST/women/NER/PH units limited to Rs. 20,000/- for booth size of 6 Sq. Mtrs. and Rs. 50,000/- for technology trade fair/ exhibition. 100% of Contingency expenditure (include travel, publicity and freight) for all categories of units subject to maximum Rs. 10,000/-.
- 4. International Trade Fairs / Exhibitions:** The Financial assistance of 80% of space rent paid for General category units and 100% for SC/ST/women/NER/PH units limited to Rs. 1.00 lakhs for booth size of 6 Sq. Mtrs. 100% of air fare, economic class for one person maximum Rs 1.25 lakhs for all category units.
- 5. International / National Workshops / Seminars on Marketing /Public Procurement /Packaging etc.:** Scale of assistance would be Rs 2.5 lakhs maximum for National Workshop / Seminar and Rs 5.0 Lakhs maximum for International Workshop / Seminar including cost of travel, boarding & lodging for international experts.
- 6. Vendor Development Programmes:** State Level Vendor Development Programme (SLVDP) will focus on Vendor-Vendee match with duration of one day and Rs. 30,000/- per programme. National Level Vendor Development Programme (NLVDP) will focus on organizing Industrial Exhibition cum Buyer-Seller Meet with duration of be 2-3 days. The maximum sanction per program would be of Rs 8.00 lakhs (max.) & minimum recovery of 60% for "A" class city; sanction of Rs 6.00 lakhs (max.) & minimum recovery 50% per program for all other cities except NE states/J&K/ Himachal Pradesh – max. sanction Rs 5.00 lakhs & minimum recovery 20% per program.
- 7. Reimbursement on obtaining Bar code:** Providing 75% of one time registration fee and Annual recurring fee (for first three years) paid by MSEs to GS1 India. The claim may be submitted in prescribed format (or system in place).



Physical/Financial progress of sub-schemes:

Name of the Scheme	Name of the Component	Physical		Financial (Rs. in lakhs)	
		Since Inception To 2013-14	2014-15 to 2016-17	Since Inception to 2013-14	2014-15 to 2016-17
Marketing Assistance and Technology Upgradation (MATU)	Domestic Trade Fairs/ Exhibitions	1622 MSMEs	1519 MSMEs	248.29	287.84
	International Trade Fair	1016 MSEs	777 MSEs	1655.00	1123.00
	International / National workshop / seminar (Formerly Export Promotion)	1777 MSMEs	3571 MSMEs	23.07	88.15
	Vendor Development Programme (VDP)	60943 MSMEs	53170 MSMEs	1249.60	1198.98
	Bar Code	3228 MSEs	2599 MSEs	471.84	439.79

MSME pavilion in IITF, 2017

IITF, 2017 is scheduled from 14 – 27 November, 2017 and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is participating, in this event.

This Ministry has been allocated Hall No. 7 D & E in ITPO, Pragati Maidan, New Delhi wherein a MSME pavilion comprising of a MSME Theme Stall to display innovative products to showcase the capability & contribution of MSME sector in Government initiative “Startup India” and 50 Micro, Small Enterprises are participating and displaying their variety of products from chemical, Handloom & Textiles, Handicraft, Sheet metal, Gem & Jewellery, Leather, Food, Herbal, health care, Electrical, fragrance & Toys Sector. The MSME pavilion inaugurated by Hon’ble MoS (I/C) for MSME.

The Ministry also participated in IITF, 2016. The details of participants is as follows:

Sl. No.	Category of participated Units	Number of units	Product Sector
1	Women	49	Handicraft, Food, Chemical, Gem & Jewellery, Leather, Furniture Woollen, Ceramics, Electronics etc.
2	SC/ST	12	
3	Minority	3	
4	General	8	
5	NER	9	

Conclusion:

The MSME of India would be the cradle for “Start up & Stand up India” vision. MSMEs are the backbone for the existing and future high growth businesses with both domestic and foreign companies. The growth of MSME enable the development of a sustainable business eco system that enables and continuously support business that are gearing to deliver the right product, the right quality, the right solution and right service at competitive price, both in domestic and international markets. ■

– *Shri Samuel is Joint Development Commissioner and CVO in the Office of Development Commissioner (MSME) and Shri Verma is Deputy Director (Exhibition).*



Indian Polymer Packaging Industry

– Nishant Jain, Dr. Sidharth Sirohi*, Dr. Balaram Pani

The major focus of polymer packaging is in FMCG (Fast Moving Consumer Goods), healthcare, food & beverages, cosmetics and toiletries. The growth in plastic packaging in India is mainly driven by food and pharmaceutical packaging. Investors are finding increased potential in India due to increased globalisation and urbanisation. According to Indian Brand Equity Foundation (IBEF) the Indian food industry which is currently valued at US \$ 39.71 billion is expected to grow at a Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of 11 per cent to US\$65.4 billion by 2018. Food and grocery account for around 31 per cent of India's consumption basket. Looking at staggering statistics of Indian food industry, the packaging sector is bound to grow. According to Indian Institute of Packaging, the size of India's food packaging market will increase from present \$ 12 billion to \$ 18 billion by 2020.

Polymers are amongst the most versatile material known to mankind. Due to its low specific gravity and high bonding strength, polymers are majorly exploited in the field of building & construction, electrical/electronics, adhesives, coating, furniture and furnishings. Polymers in packaging application have outpaced the growth in other sectors because of its superior properties than its other counterparts such as glass, metal, paper or paperboard as shown in Figure 1. Packaging is one of the fastest growing industries and stands at \$ 700 billion globally and according to FICCI and TSMG statistics, the Indian Packaging Industry will reach \$72 billion by 2020.

The packaging industry is divided into two segments: rigid and flexible packaging as shown in Table 1. The packaging industry is shifting its gears towards flexible packaging due to its light weight, attractive look, reduced space requirement, easy stacking and low transportation cost. The packaged product should be consumer friendly and easily adaptable. The industry is focusing on innovative ideas in the field of flexible packaging in order to make the product attractive, saleable & easy to handle. The major advantage of such

kind of packaging is that it comes in various shapes and sizes involving retort pouches, flat pouches, wraps, gusseted bags, sachets etc. Starting from packaging of F&B products, fruits and vegetables, medicinal products, home and personal care products to highly dangerous and heavy industrial products, the Packaging industry has led to greater specialisation over a period of time. The Indian flexible packaging market is expected to grow to \$32 billion by 2020.

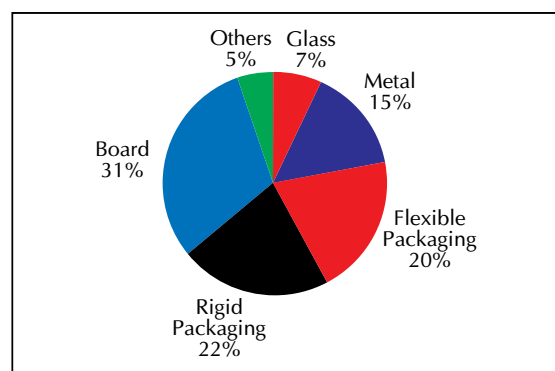


Fig 1. Global segment breakup of packaging materials (%)

Source:-FICCI, Plastic Packaging: A sustainable Choice 2016

Table 1. Classification of Polymer Packaging Industry

Classification	Type	Application
Flexible packaging	Aluminium Foil	Direct contact wrapping-chocolate & individual sweets
	Blister and Strip Pack	“Blistered” chilled processed meat and fish/seafood products, beauty & healthcare products
	Flexible/Aluminium Paper	Packaging of butter, baby food, dehydrated soups and sauces, hot drinks etc.
	Flexible Aluminium/Plastic	Dog & cat food, shampoos, liquid soaps, mouth fresheners
	Flexible Paper	Smoking tobacco, sugar confectionery (such as toffees) and some cheese products
	Flexible Plastic	Confectionery, bakery products, dry dog and cat food, disposable paper products, frozen food, snacks, pasta and rice
Rigid Packaging	High Density Polyethylene (HDPE) Bottles	Milk containers, shampoo bottles, toilet cleaners etc.
	Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles	Carbonated drinks, water bottles, juices etc.
	Ready Meal Trays	Made of crystallised PET- used in microwave proof disposable cutleries
	Speciality cosmetic containers	Compacts used for eye shadow and powders and lip stick mechanisms

The major focus of polymer packaging is in FMCG (Fast Moving Consumer Goods), healthcare, food & beverages, cosmetics and toiletries. The growth in plastic packaging in India is mainly driven by food and pharmaceutical packaging. Investors are finding increased potential in India due to increased globalisation and urbanisation. According to Indian Brand Equity Foundation (IBEF) the Indian food industry which is currently valued at US \$ 39.71 is expected to grow at a Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of 11 per cent to US\$65.4 billion by 2018. Food and grocery account for around 31 per cent of India's consumption basket. Looking at staggering statistics of Indian food industry, the packaging sector is bound to grow. According to Indian Institute of Packaging, the size of India's food packaging market will increase from present \$ 12 billion to \$ 18 billion by 2020. Fruits and vegetables are going

to lead this growth story. Multilayer packaging and aseptic packaging are brimming technologies in the field of food packaging. India's largest flexible packaging company Uflex Pvt. Ltd. will invest Rs. 550 crores under “Make in India” mission in aseptic packaging proposing to produce around 7 billion packs of liquid drinks such as energy drinks, milk and juices.

The Indian pharmaceuticals market increased at a CAGR of 17.46 per cent in 2015 from US\$ 6 billion in 2005 and is expected to expand at a CAGR of 15.92 per cent to US\$ 55 billion by 2020. The Indian packaging industry will be benefitted by such an impressive growth in the pharmaceutical industry. Packaging of such products is essential as it would ensure the safety and prevent the contamination of the enclosed product. India have varied climatic conditions ranging from extreme



cold in north to hot & humid in south. These factors compel the selection of the right type of packaging materials and processes to maintain the stability of a drug. Due to high humidity and disproportionate temperatures existing in different parts of our country, it poses a great challenge to select the most suitable and optimum package to achieve the desired shelf-life.

Polyesters, High Density Polyethylene (HDPE), Low Density Polyethylene (LDPE), Poly (vinyl chloride) (PVC), Polypropylene (PP) are majorly used in the packaging of oral drugs, IV drugs, injectables, blood bags, nasal spray, eye drops etc. Some of the speciality polymers such as Poly (vinylidene chloride) (PVDC), Ionomer and Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH) are used in coatings improving the functional properties of basic packaging material (Table 2). These speciality coatings provide specific properties such as high barrier to oxygen, moisture aroma/flavour or it may impart sealability to a package even when its surface is contaminated by the product. With growing population and increasing medical conditions, pharmaceutical packaging industry will have direct growth impact.

Table 2. Polymers in Pharmaceutical Applications

Type	Polymer used	Application
Strip Packaging	Aluminium Foil/LDPE Aluminium Foil/Heat Seal Lacquer (HSL) Glassine/LDPE	Insulin Cartridges
Blister Packaging	Aluminium Foil/PVC PVDC coating	Tablets & capsules
Plastic Jars & Bottles	PET, HDPE, PP	Tablets & capsules, liquid orals, dry syrups, oral hygiene, lotions, nasal sprays
Pouches/ Sachets	Paper/ foil/ LDPE	Transfusion solutions
Squeeze tubes/ Plastic collapsible tubes	Multilayer packaging using PE and PP	Ointments and ceramics

The global pharmaceutical packaging market is projected to witness a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of approximately 8% in the coming five years (2015-20). Due to increasing generic and contract manufacturing activities in Asian countries especially India and China, the emerging geographies are expected to register maximum growth. Indian market is expected to grow at a CAGR of 18% by 2020.

The Indian healthcare sector is growing at a Compound Annual Growth Rate of 15% for the next five years and is projected to become a US\$155 billion market by 2017, at which point it will be among the largest revenue-generating sectors in India, according to The Economic Times, Times of India. There are many accelerators and catalysts for the healthcare packaging market in India. The government has allowed 100% Foreign Direct Investment in the medical device sector. Foreign investors no longer have to go through the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) for permission, which was a cumbersome and time-taking affair. Clariant plans to invest CHF 10 million in a new healthcare packaging manufacturing plant in Cuddalore in Tamil Nadu State. The plant will manufacture Clariant's moisture control products. The future of healthcare packaging in India is bright and that is underlined by the fact that many healthcare packaging giants are setting up their plants in India.

India is a major exporter of plastic and plastic products which includes plastic raw materials, packaging items, woven sacks / FIBCs, medical disposables, writing instruments, floor coverings, houseware. Ministry of Commerce reported the total export of plastic products US\$ 449.72 million in May 2015. India is striving as one of the major plastic packaging material exporters of the world. Packaging has an annual global turnover of about \$550 billion, and India's share is about \$16.5 billion per annum. According to the Mckinsey report, the middle class population of India will increase ten folds by 2025 which will further increase the consumption of the plastic packaging



material. Smithers Pira (UK based firm) expects the global market for flexible packaging is forecast to grow at an annual average rate of 3.4% during the period 2015-2020, reaching \$248 billion. Indian packaging industry is growing at a rate of about 15-18 percent annually. The exponential growth is also attributed due to increase in working women and advent of fast on-door delivery of food items and other products which is triggered by home-grown e-commerce companies like Snapdeal, Flipkart, PayTM etc. E-commerce is now a booming sector in India, and depends on corrugated packages, which is expected to further aid the growth in the packaging industry

The major contributors of Indian Packaging Industry are Uflex, Essel propack, Balmers Lawrie & company limited, Max India. Ltd, Ester Industries etc. The emergence of in-house FMCG manufacturers such as Baba Ramdev's Patanjali has caused a stir in the packaged consumer goods sector. The company comprises of 12 successful running units including units for Packaging material and Containers. The company's co-packaging facility are Tetra Pak and Volpack. Patanjali employs more than 6000 labourers, more than 400 sales staff, 300 technically qualified employees and provided more than 2.0 lac indirect employment. The company reported Rs. 5000 crore net sale in the business year that ended on 31 March, 2016 and expects Rs. 10,000 crore net sale in the next year. Baba Ramdev's initiative has changed the syntax of the FMCG business as he aims Rs. One Trillion (\$14.9 billion) net sale in coming 10 years.

As the reported by Pack Pluss 2016, the Indian Packaging Industry is expected to triple to around \$60 billion in next five years. Indian packaging machinery are growing rapidly comprising of approximately 600-700 machinery manufacturers, 95% of which are small and medium sector located all over India. Some of the major domestic equipment manufacturer suppliers are Flex Engineering Ltd., (Noida), ITW Signode India Ltd. (Hyderabad), Print Pack Machinery Ltd. (Faridabad), Eagle Manufacturing Co. (Mumbai),

Larsen & Toubro for various type of packaging machinery. The Indian Packaging machinery imports are \$125 million.

With the poignant growth of the packaging industry, employment is also generated. "Make in India" mission initiated by Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, aims to convert India into global manufacturing hub. The mission will enhance the infrastructure by bringing in foreign investors. The 'Make in India' campaign will trigger the Manufacturing industry which will further trigger the consumption of packaging material. This in turn will bring direct demand for packaging development executives, supply chain professionals, quality controllers and factory managers. An export-oriented plastic cluster has been proposed to be set up at an investment of over Rs 100 crore in Lucknow. India Industries Association (IIA) in collaboration with CIPET will set up this cluster. Cluster has already generated interest amongst 200 industrialists and entrepreneurs and is expected to generate direct employment opportunity for ~2,500 youth. The Indian industry has the potential to increase considerably. High growth in retail packaging, pipes, bulk packaging and agricultural use has triggered the polymer demand thus increasing the employment opportunities.

Indian packaging Industry is evolving and growing every year. The industry is carving its own niche by introducing innovative ideas, sustainable solutions by adoption of new technologies and eco-friendly solutions. The incessant growth of the industry is due to sharp rise in end-user industry, dynamically changing lifestyles, availability of feedstock and focus on manufacturing.

**Corresponding Author & Asstt. Professor,
Bhaskaracharya College of Applied Science (University of Delhi)*



Celebration of First United Nations Micro, Small and Medium – sized Enterprises Day and distribution of National Awards-2015

– Dr. Om Parkash Mehta

The memories of the National Awards function held on 18 October 2016 that was presided by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi at Ludhiana had not yet been vanished in the minds of masses and the Government of India again recognised good management practice of giving incentives (financial & non-financial/recognitions) of the efforts/works of people and enterprises for the splendid cause and public spirit that played an important role in their existence and further achievements (scale up, expansion and innovation etc.) in a short interval of time that was repeated on 27 June 2017 in New Delhi.

2. Government of India through its Office of the Development Commissioner (MSME), an attached office in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) recognized the contribution of entrepreneurs of MSME sector on the first auspicious occasion of United Nations Micro, Small and Medium – sized Enterprises (UN MSME) Day celebrated worldwide on 27 June 2017 by giving them National Awards. Although, it was not the first occasion that the National Awards were given to MSMEs for their outstanding contribution in MSME sector as these awards have been regularly given by the Office of the Development Commissioner, Ministry of MSME yearly since these had been instituted in the year 1983, yet this year the function was unique in many respects. Government selected the occasion coinciding with first UN MSME Day to express the gratitude of the Government to the achievers in the MSME field which is so important for the national economy. and the day was celebrated with distribution of the National Awards along with other activities. Another unique feature was that the awards were given exclusively to entrepreneurs of MSMEs as

on previous year awards for KVIS and Coir sector were also used to be given on same day. Number of awards were also increased manifold in various categories i.e., by including dibayangs as well as also export sector inter alia.

3. Recognizing the importance of micro-, small- and medium-sized enterprises in achieving the new global development goals, the United Nations General Assembly designated 27 June as International Day for those actors. In a resolution adopted without a vote, the 193-member body also invited all stakeholders, including Member States, UN entities and civil society organizations, to observe the Day and raise public awareness of their contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development, which the Assembly adopted in September 2015. The resolution was introduced by the delegation of Argentina, with its representative stating that more than 95 per cent of enterprises in the world are micro-, small- and medium-sized and they account for about 60 per cent of private sector employment. "These enterprises can in fact become the engines that sustain growth for long-term development in developing countries," the representative said, thanking the contribution made by the International Council for Small Business (ICSB) to the creation of the Day. ICSB held its 61st Annual World Conference at United Nations last year, in which authorities from over 55 countries participated. In that occasion, ICSB made a declaration about the urgent need to have a day to recognize the important role of micro, small, and medium enterprises in the development of economies as a whole.

4. The glittering function was held at Pravasi Bhartiya Kendra, New Delhi which was presided



by Shri Kalraj Mishra, the then Union Minister for MSME in the presence of Shri Giriraj Singh and Shri Haribhai P. Chaudhary, Ministers of State for MSME, Shri KK Jalan, the then Secretary MSME, Shri Surendra Nath Tripathi, the then Development Commissioner and other dignitaries of the Ministry.

5. On this occasion the Hon'ble Union Minister for MSME Shri Kalraj Mishra handed over three Memorandums of Understandings to SAP India, Intel and HMT and also launched 'Digital MSME Scheme'.

6. Memorandum of Understanding (MoU) with SAP – The SAP India has redesigned one ERP software namely, Bharat ERP (B-1) which is suitable for small size enterprises. The SAP will provide handholding support, curriculum, licensing software, training of trainers initially to 5 Technology Centres at Jamshedpur, Hyderabad, Bhubaneswar, Mumbai and Aurangabad. The infrastructure, training of trainers will be provided by the Technology Centres. This training will not only help in providing cost effective ERP training to MSMEs and unemployed youth but will also provide branding and ERP orientation to the MSME Technology Centres.

7. MoU with INTEL India – INTEL Technology India Private Limited is a technology joint and will help the MSME field organizing in providing training curriculum, training of trainers etc. in the field of IOT (Internet of Things), ESDM, VLSI, Chip design. The INTEL will also initiate GST to afford implementation of GST to MSMEs apart from creating awareness on GST. The association with INTEL will help the MSMEs in adopting the state-of-the-art technology and GST as well as with Technology platforms.

8. MoU with HMT (International) Ltd.– This MoU was signed towards extending the existing MoU with Technology Centre, Bhubaneswar for supporting HMT (International) Ltd. in providing skill upgradation, training of trainers etc. in their overseas assignments. The trainers from MSME Technology Centre are deputed for providing skill

upgradation training. The MoU can also be further extended to enhance its scope for skill upgradation activities.

9. Launch of Digital MSME Scheme for Promotion of Information and Communication Technology (ICT) in MSME Sector: The scheme is revolving around Cloud Computing which is emerging as a cost effective and viable alternative in comparison to in-house IT infrastructure installed by MSMEs. In cloud computing, MSMEs use the internet to access common as well as tailor-made IT infrastructure including software for managing their business processes. The common benefits of Cloud Computing approach are:

- i. Cloud computing is free from the burden of investment on hardware/software and infrastructural facilities. Therefore CAPEX converts into OPEX.
- ii. It follows "pay as you use" model and the user does not have to invest upfront.
- iii. The initial cost to use specific services gets reduced substantially.
- iv. The Cloud Computing operations are readily scalable. The user can access various services depending upon the requirements.
- v. The use of Cloud Computing facilitates device and location independent access.
- vi. Maintenance / updation of Software is not the responsibility of the users.

10. Various components of the scheme include organizing awareness programme, workshops and publicity; to provide assistance to MSMEs to use Cloud computing services etc., The details of the scheme are available on official website of O/o DC(MSME) at www.dcmsme.gov.in

11. The above celebrations were followed by distribution of 56 awards to MSMEs (including 6 for banks). The award to MSMEs comprised of Rs. One lakh in cash, a certificate and a trophy to



each awardee. On this occasion National awards were also given to banks for their outstanding contribution in the MSME sector and each award comprised of a certificate and trophy.

12. The list of awardees of National Awards - 2015 is given as under:

National Awards – 2015



S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
Product/ Process Innovation-Micro & Small Enterprises		
1	First Award	Pawan Kumar Goel M/s Chemical Resources Plot No. 3A, Industrial Area, Phase-2, Panchkula, Haryana-134109.
2	Second Award	Siddhartha Chatterjee M/s Sarada Robotech Vill & PO- Chamrail, PS- Liluah, Howrah, West Bengal

S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
3	Third Award	Samir Kumar Neogi M/s Neogi Technologies And Research Pvt. Ltd. 2 Kumarpara Road, PO-Rajpur,PS- Sonarpur, South 24-Pargana, West Bengal
4	Third Award	Kailash Movaliya, M/s Captain Tractors Pvt. Ltd., Padavala Road, Veraval (Shapar), Kotda Sangani, Rajkot, Gujarat.
Product/ Process Innovation- Medium Enterprises		
5	First Award	Vikram Singh Bhadauria M/s Alok Industries C-65/1, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
6	Second Award	Tushar Jain M/s Automat Irrigation Pvt Ltd. Plot No. 4-5 Sector 3A IIE Ranipur SIDCUL Haridwar, Uttrakhand
Outstanding Entrepreneurship (Mfg.) - Micro Enterprises		
7	First Award	P S Pramanick M/s Laxman Group of Engineers Bazarpara, Uluberia, Howrah, West Bengal
8	Second Award	Indrojit Dutt M/s Monorama Dairy & Foods (P) Ltd Bighati (Delhi Road), Bhadreswar, Hooghly, West Bengal,
9	Third Award	Vikram Luthra, M/s Life Style Foods Pvt Ltd. 508, HSIIDC, Food Park, Rai Industrial Area, Sonipat, Haryana.
Outstanding Entrepreneurship (Mfg.) – Small Enterprises		
10	First Award	Rajeev Sardana, M/s Yamuna Cable Accessories Private Limited, Sardana Nagar, Ambala Road, Jagadhri, Yamuna Nagar, Haryana
11	Second Award	Kailesh Movaliya, M/s Captain Tractors Pvt. Ltd., Padavala Road, Veraval (Shapar), Kotda Sangani, Rajkot, Gujarat.
12	Third Award	Rohit Agarwal, M/s Prabhu Poly Pipes Limited, Sankrail Industrial Estate, Sankrail, Ward- Kanduah, Howrah, West Bengal.

S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
13	Special Award to Women Entrepreneur	Apolo Das, M/s Gold Magenta Hospitality Products & Services Private Limited, Basai, P.O. Kanaipur, Hooghly, West Bengal.
14	Special Award to SC/ST Entrepreneur	Rajkumar Singh, M/s Marshal Enterprises, I-97, Yamunapuram, Bulandshahr, Unit-1, R-59, UPSIDC, Sikandrabad (UP)
Outstanding Entrepreneurship (Mfg.)- Medium Enterprises		
15	First Award	T. Valsaraj, M/s Coastal Corporation Ltd., #15-1-37/3, Nowroji Road, Maharanipeta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh
16	Second Award	Rajendra Malviya, M/s Asha Confectionary, 11/A, 11/B & 12/A, Sanwar Road Industrial Area, Indore, M.P.
17	Third Award	Ravi Poddar, M/s Cheer Sagar, E-194, Industrial Area, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan.
Outstanding Entrepreneurship (Services) Micro & Small Enterprises		
18	First Award	Samir Tripathi, M/s Medhaj Techno Concept Pvt. Ltd. CP 150, Sector D-1, Ashiyana, Newar Power House Crossing, Lucknow, Uttar Pradesh.
19	Second Award	Patil Arunkumar C, M/s Cadmaxx Solutions Pvt. Ltd., #2095, 5 th Main, 9 th Cross, R.P.C. Layour, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka-560040.
20	Third Award	Vijay Mehta, M/s A V Global Corporation Private Limited, 201, New Delhi House, Barakhamba Road, New Delhi.
Lean Mfg. Techniques – Small Enterprises		
21	First Award	Rajendran N. M/s Bestomech Industries, SFNo. 912/3B, apupparayanpalayam, Mylampatti, Coimbatore, Tamil Nadu.

S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
Lean Mfg. Techniques –Medium Enterprises		
22	First Award	Vimal Chand Jain, M/s Precision Auto castings Private Limited Plot No. 9, Udyog Vihar, Road No. 17, V.K.I. Area, Jaipur, Rajasthan.
Quality Products		
23	Paints & Varnishes- First Award	Suyash Singhal, M/s Surface Paints Private Ltd., B-736, Sector-C, Mahanagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
24	Rubber Molded Products – First Award	R. Sundaram M/s Aerospace Engineers, The Salem Aeropark, NH7, Ammalalayam Village, Mallur, Salem, Tamil Nadu.
25	Precision Machine Component – First Award	Gaurav Malhotra, M/s Presto Stantest Private Limited, I-42, DLF Industrial Area, Phase-1, Faridabad, Haryana.
26	Metal Auto Component – First Award	Mangeram, M/s Durga Filters Pvt. Ltd., D-48 &49, Sector A-2, Tronica City, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
27	Electronic Smoke Detectors/Fire Alarms/ Pollution Detectors and Monitors – First Award	M. Kalaichellvan, M/s Manatec Electronics Pvt. Ltd., C-22 & 23, Industrial Estate, Thattanchavady, Puducherry.
28	Refractory – First Award	Ghanshyam G. Dholaria, M/s Noble Refractories, 27 National Highway, Village Hasanpar, Wankaner, Morbi, Gujarat-363622.
29	Confectionary Products – First Award	Apolo Das, M/s Gold Magenta Hospitality Products & Services Private Limited, Basai, P.O.: Kanaipur, Hooghly, West Bengal.
30	Leather Hand Bags - First Award	Suman Chawla, M/s V & M, Plot No. 47, Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana.



S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
31	Readymade Garments- First Award	Komal Kumar Jain, M/s Duke Fashions (India) Limited, G.T. Road, Near Jalandhar By-Pass, Ludhiana, Punjab-141008.
Outstanding Export Performance –Micro (Mfg)		
32	First Award	Bhaskar Sharma, M/s Sharma Artistic Stone Gallery, 10 Lata Kunj, Mathura Road, Agra, Uttar Pradesh.
Outstanding Export Performance – Small (Mfg.)		
33	First Award	Sudip Basu, M/s PCL Foods Private Limited, Ramba Road, Taraori, Karnal, Haryana-132116.
34	Second Award	Ashish Singh, M/s God Gift International, 505-508, Peetal, Nagri, Rampur Road, Moradabad, Uttar Pradesh.
35	Second Award	Pawan Kumar Goel, M/s Chemical Resources, Plot No. 3A, Industrial Area, Phase-2, Panchkula, Haryana-134109.
36	Best Exporter Award to Women Entrepreneur	Parmeshwari Mundra, M/s Nirmal Glasstech Industries, F-370-371, Road No. 9 F, V.K.I. Area, Jaipur, Rajasthan.
Outstanding Export Performance – Medium (Mfg.)		
37	First Award	T. Valsaraj, M/s Coastal Corporation Ltd., #15-1- 37/3, Nowroji Road, Maharanipeta, Visakhapatnam, A.P.
Product Specific Outstanding Export Performance – Micro, Small & Medium Enterprises		
38	Leather Hand Bags - First Award	Anil Kumar Moti, M/s Paradigm Leather Accessories, Plot No. 194, Sector-6, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana.
National Awards to Banks for Excellence in MSE Lending		
39	First Award	Bharatiya Mahila Bank
40	Second Award	Indian Bank
41	Special Award	State Bank of Travancore

S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
National Awards to Banks for Excellence in Lending to Micro Enterprises		
42	First Award	Indian Bank
43	Second Award	IDBI Bank
44	Special Award	State Bank of Hyderabad
Dibyang – (Physically Handicapped) in Micro Enterprises (Mfg.) – Special		
45	First Award	P. Guna Shekar, M/s P. P. Enterprises, NO.133, Ground Floor, 3 rd A Cross, 2nd Main Road, Prakashnagar, Bengaluru, Karnataka – 560021.
Outstanding Efforts in Small Entrepreneurship (Mfg.) – NER		
46	First Award	Basant Kumar Khetan, M/s Necon Power and Infra Ltd., Industrial Estate, Cinnamara, Jorhat, Assam
Dibyang – (Physically Handicapped) in Small Enterprises (Mfg.) – Special		
47	First Award	Praveen Rastogi, M/s Natural Herbals & Seeds, C/o Continental Seeds & Chemicals Ltd., Ramraj Road, Bazpur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand.
Outstanding Entrepreneurship (Services) – Micro & Small Enterprises – Special Award to Divyang		
48	First Award	Ashok Kumar Pareek, M/s Lado Cad Technology, 1 st Floor, Morija House, Main Kanta Chouraha, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
Quality Products (LED and LED information Display System)		
49	First Award	Ayush Aggarwal, M/s Infosoft Digital Design and Services Pvt. Ltd. 484, Sector- 8, IMT, Manesar, Gurgaon, Haryana.



S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
Outstanding Export Performance – Small Enterprises (Mfg.) – SC/ST		
50	First Award	Venkatesh D T, M/s Growell CNC Systems, C-438, 1 st A Main Peenya Industrial Area , Bangaluru, Karnataka
Outstanding Export Performance – Medium Enterprises (Services)		
51	First Award	Vinod Sood, M/s Hughes Systique Corporation, D-24, Info City-2, Sector-33, Gurgaon, Haryana.
Outstanding Export Performance – Micro, Small & Medium Enterprises – Product Specific		
Paints & Varnishes		
52	First Award	Dr. Harinder Bir Singh Lamba, M/s Wembley Paints and Chemicals, Plot No. 1078, MIE Part-1, Bahadurgarh, Haryana.
Rubber Molded Products		
53	First Award	K.J. Louis, M/s Highrange Rubber and Coir Products, Shed No. 13/298, Industrial Estate, Kottayam, Kerala.

S. No	Categories of Awards	Name & Address (S/ Shri/ Ms)
Precision Machine Component		
54	First Award	Parmeshwari Mundra, M/s Nirmal Glasstech Industries, F-370-371, Road No. 9 F, V.K.I. Area, Jaipur, Rajasthan.
Electronic Smoke Detectors/ Fire Alarms/ Pollution Detectors and Monitors		
55	First Award	Amit Gujral, Encardio-rite Electronics Private Limited, A-7, Industrial Estate, Talkatora Road, Lucknow, UP.
Readymade Garments		
56	First Award	Samta Khanna, M/s VNS Accessories (India) LLP, Plot No. 441, Udyog Vihar, Phase-4, Gurgaon, Haryana-122015.

13. To conclude, the coordinated efforts of the Government, officials and all agencies that made the above event a successful in a short span of time. It will motivate the entrepreneurs of MSME sector to prove their excellence world-wide. It will not go in vain in the time to come and will show a path for others to excel in the field. ■

– Dr. Om Parkash Mehta is Director (Budget/National Award) in the Office of the Development Commissioner (MSME).



Waste Human Hair converted into Novel Agro nutrients

Project implemented by MGIRI

– Dr K.R. Yadav

Introduction

Millions tones of small hair is generated from the hair cutting saloon on average of 120 crores population of our country. Based on survey conducted by bio- processing and herbal division of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI) at Wardha, normally an individual's visit hair cutting saloon every year 4-5 times in a year to cut the hair and on an average 20-25 gm hair is generated and getting waste. Based on this estimation every year approximate 2500-3000MT hair available at free of cost. Hence a suitable technology to be developed for the above waste and make the environment neat and clean generate the employment for the Indian youth based on this waste. Keeping the above in the mind bio-processing and herbal division of MGIRI, Wardha has developed low cost technology based on the above waste to wealth and creating an employment to the Indians youth and also making significant contribution towards Swachha Bharat mission as it was the dream of our father of the nation, Mahatma Gandhi ji and presently the our honourable Prime Minister of India.

Factors governing the choice of waste human hair as a raw material for plant growth promoter (amino acids mixture) production:

Human hair waste from millions of people thrown as a municipal litter is unhygienic condition spread bacterial and fungal diseases. Its general uncleanliness posed serious health problems. Its use in PGP preparation will minimize these problems.

- It is not easily bio-degradable and hence caused problems of its safe disposal in municipal refuge.
- While nobody ever bothered to use hair waste,

through this R&D it is attempted to examine if the problems of disposal of human hair could be converted into a socially acceptable opportunity and make some contribution towards Swachha Bharat Mission.

- It is the richest (90-95%) source of protein or 14-15% organic nitrogen and source of organic carbon.
- Due to its high protein content output of PGP/ kg of human hair processed will be maximum in the same equipment, energy, consumption of chemicals, labour and time spent.
- It is economically available from rag pickers at the rate of Rs. 3-4 thousands per metric tone (MT).
- Human hair waste from hair cutting saloons choked the drainage system. Its use will solve this environmental problem.
- The vital point in its selection was that it was equal or superior to other proteins in the parlance of plant physiology.
- As a cumulative effect of the above mentioned factors, it was decided to explore the use of waste human hair as a starting raw material for the production of PGP.

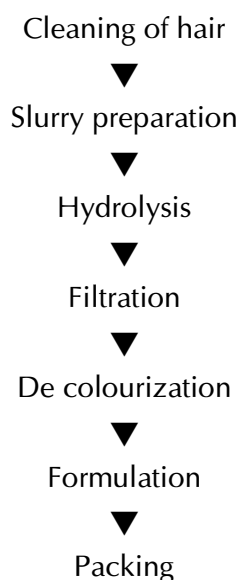
Method of preparation of amino acids mixture from waste human hair

The hairs were clean, dried and hydrolyzed by as per the standard method of protein hydrolysis using commercial grade catalyst, (mineral acid). The hydrolysis process was monitor using Birute/ TCA test to know the complete hydrolysis. After completion of hydrolysis, the hydrolysate was cooled and pH was adjusted immediately using



metal oxide/carbonate and filters under vacuum using Decamole over a Buchner funnel and filter cloth. After pH adjustment the hydrolysate was subjected to charcoal treatment and finally filters under vacuum using decamole. Finally the filtrate was taken for formulation with glycerol to avoid crystallization. The whole protocol needs around 7-8 hrs, getting around 95% recoveries in a reproducible manner in the form of mixture of amino acids

Process flow chart diagram of the product:



Specification of the product:

- I) Physical appearance : Dark golden yellow clear liquids
- II) Specific gravity : 1.2 ± 0.1 .
- III) pH : 3.5 ± 0.1 ,
- IV) Dissolved solid : $40 \pm 1\%$,
- V) Amino nitrogen : $4.0 \pm 0.1\%$,
- VI) Total nitrogen : $7.0 \pm 0.5\%$,
- VII) Organic carbon : $8.0 \pm 0.5\%$,
- VIII) Total amino acids mixture : $13.0 \pm 0.5\%$.

Applications and Doses and shelf life of the product: For all crops in agriculture, horticulture and flowery culture, this can be applied at the rate of 1.5-2.0 litre per acre in 200-250 litre water through foliar spray or through drip irrigation. The shelf life of the product is 3 years from the date of manufacturing

Field trials: Field trials have been carried out by 200 farmers in Vidarbha region on cotton, chilli, Chana, Tur, Soyabean and Turmeric. The results are encouraging in terms of crops health and yield. The yield has gone up to 20-25% compared to normal crop.

Enterprise & training provided: Participants from various states e.g. Maharashtra, Bihar, Gujarat, Tripura, Andra Pradesh, Uttar Pradesh, Uttra Khand, Delhi, Haryana, and Madhya Pradesh. Total no. of training provided 150 youths for the production of noble agro-nutrients based on waste hair and 35 nos have started their business in this area. Recently with the help District collector, Wardha in collaboration with Agriculture Technical Management Agency (ATMA) and MGIRI has developed 20 enterprises In Wardha district by providing 20 lakhs.

DC-MSME has also provided an incubation programme for the same to Mr Amol Boinkinpillewar from yavatmal based entrepreneur and he has started producing the plant growth promoter and earning 8-10 lakhs /annum.



Cleaning of hair with detergent and tap water





Sun drying of hair after cleaning during training programme.



Dr K.R. Yadav explaining the Sun drying of hair to DG MPCST on perforated sheet after cleaning the hair during training programme.



Filling of cleaned hair in the reactor for hydrolysis



A few entrepreneur developed by MGIRI under Swachha Bharat Mission from waste hair

Waste hair converted in to wealth

Finish product

Hairamin a Plant growth promoter from waste human hair technology developed by MGIRI



Photos from Maan biotech, Nalgonda Dist. Telangan state an entrepreneur of MGIRI



- The Writer is Deputy Director in MGIRI, Vardha

Trade Fair/VDP – an initiative of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises to provide marketing support/ platform to MSEs

– H.S. Bisht

Introduction:-

Micro, Small and Medium Enterprises are vibrant sector in Indian economy and plays a vital role in over all development of the country. MSMEs have shown constant growth rate of over 10.8% in recent years. This sector contributes 37.54% (including service) of the country's GDP, 45% of the manufactured output and more than 40 % of its exports. The MSMEs provide employment to more than 113 million persons through 63.4 million enterprises which producing over 8000 products. "Make in India", "Skill India", "Digital India", "Start ups, IPR, Incubation, green India, Zero Defect and Zero Effect (ZED) are some of the area being focussed by this Ministry for the growth and development of the MSME sector.

Initiative for providing marketing support

Office of the Development Commissioner, Ministry of MSME is having a scheme of Marketing Assistance & Technology Upgradation (MATU) for promotion of MSME Sector. The details of the modified scheme ie. Marketing Assistance and Technology Upgradation (MATU) is available under the Marketing Assistance Icon of this office link www.dcmsme.gov.in. The scheme is under operation w.e.f the 29th June, 2016. The highlight of the scheme is as under:

i) Objective of the scheme:

- To encourage manufacturing Micro and Small Enterprises (MSEs) in their efforts of tapping and developing domestic/overseas markets.
- To encourage Micro and Small Enterprises (MSEs) for adoption of bar coding on products

for increase in marketability of products in National/International market.

- To facilitate marketing linkages especially in the view of Public Procurement Policy for MSEs Order 2012.
 - To create consciousness and to educate the MSEs about importance of packaging in marketing, latest packaging technique, import- export policy and procedure, latest development in international trade etc by organising International & National Workshop/Seminar on marketing/packaging/ topics relevant to MSME sector.
- ii) **Eligibility Criteria:** The applicant Micro/Small Enterprise should suitably be registered through EM part II/Udyog Aadhar Memorandum(UAM) for availing financial benefits.
- iii) **Component of the scheme**
- Domestic fairs/exhibitions
 - International trade fairs/exhibitions
 - International/national workshop / seminars
 - Vendor development programme
 - Bar code

- Domestic Trade Fairs/ Exhibitions:** To encourage manufacturing Micro and Small Enterprises (MSEs) in their efforts of tapping and developing domestic markets. MSME Development Institutes act as the Implementing Agency. Under the scheme financial assistance of 80% of space rent paid for General category units and 100% of SC/ST/Women/NER/PH units limited to Rs.20,000/-



or actual whichever is less. The space rent will subject to maximum booth/stall size of 6 Sq. Mtrs. or minimum booth/stall size provided by the fair organiser.

In case of technology trade fair/exhibition, maximum limit of space rent charges will be Rs. 50,000/- in place of Rs. 20,000/-. 100% of contingency expenditure for all categories of units subject to maximum Rs. 10,000/- or actual, whichever is less (travel expenditure for one representative from each participating unit).

b) International Trade Fairs/Exhibitions: To encourage manufacturing Micro and Small Enterprises (MSEs) in their efforts of tapping and developing overseas markets. MSME Development Institutes act as the Implementing Agency. The financial assistance to MSEs is 80% of the space rent for General Category units whereas 100% for SC/ST/Women/NER units subject to maximum Rs. 1.00 lakh or actual rent paid, whichever is less. The space rent will subject to maximum booth/stall size of 6 Sq. Mtrs. or minimum booth/stall size provided by concerned Indian Trade bodies (e.g. ITPO, FIEO etc.) or the Fair Organiser. 100% of the economy class air fare for all categories of units subject to maximum Rs. 1.25 lakh or actual air fare paid, whichever is less (for one representative from each participating enterprise).

c) International/National Workshops/Seminars on Marketing/ Public Procurement/Packaging etc: International/National Workshops/Seminars on Marketing/Packaging are being organised for promotion of new marketing techniques, emerging global marketing/product innovation trends in various product and services verticals, development in packaging, reviewing public procurements with Central Ministries/ Departments/Central Public Sector Undertakings (CPSUs) under Public Procurement Policy for MSEs Order 2012 and topics relevant to MSME sector. Scale of assistance would be Rs. 2.5 lakhs per National Workshop/Seminar any where in the country (or actual whichever is lower) and Rs. 2.5 lakhs per International Workshop/Seminar in the country with an additional cost of

Rs. 2.5 lakh (maximum) towards cost of air travel, boarding and lodging etc. for international experts (or actual whichever is lower) subject to condition that International Workshop/Seminar should not be held in any Five Star Hotel. MSME Development Institutes or any other agency approved by O/o. DC-MSME depending upon the need of the event is the Implementing Agencies.

d) Vendor Development Programmes: Vendor Development Programme provides a common platform for buyer and sellers including displaying the products and service of MSMEs and requirements of large scale buyer organisations. The significance of Vendor Development Programmes has increased manifold in view of the Public Procurement Policy for MSEs Order 2012. Provision for financial assistance to the tune of Rs. 30,000/- per programme for State Level Vendor Development Programme and Rs. 8.00 lakh for "A Class cities", Rs. 6.00 lakh for all other cities and Rs. 5.00 lakh for any States/J&K/Himachal Pradesh has been kept for National Level Vendor Development Programme. MSME Development Institutes are the Implementing Agencies

e) Reimbursement on obtaining Bar Code: To provide financial assistance to Micro & Small Enterprises (MSEs) enhance their marketing competitiveness by obtaining Bar Code registration of GS-1. Financial assistance of 75% of one time registration fee and annual recurring fee (for first three years) paid by MSEs to GS1 India. The claim may be submitted in prescribed format (or system in place). GS1 India, formerly EAN India, an autonomous body under Ministry of Commerce & Industry, Government of India, is authorized for granting registration for use of Bar Codes. Other details on Bar Code are available on their website: www.gs1india.org. Interested MSEs may approach the GS1, India for getting registration for use of Bar Codes. MSME Development Institutes are the Implementing Agencies.

iv) International Co-operation (IC) Scheme:

The important objectives of the Scheme are



Technology infusion and/or upgradation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), their modernization and promotion of exports. The IC scheme including the application form is available on the website of this Ministry viz. <http://msme.gov.in>. The Scheme encompasses following activities:

- Deputation of MSME business delegations to other countries for exploring new areas of technology infusion/upgradation, facilitating joint ventures, improving the market of MSMEs products, foreign collaborations, etc.
- Participation by Indian MSMEs in international exhibitions, trade fairs and buyer seller meets in foreign countries as well as in India, in which there is international participation.
- Holding international conferences and seminars on topics and themes of interest to the MSMEs.

Under the Scheme, financial assistance is provided to the industry associations/institutions/agencies of the States/Central Government for the activities mentioned above.

V) India International Trade Fair :-

Besides above every year India international trade fair is also organised at Pragati Maidan New Delhi wef 14th Nov-27th November. This year it will be 37th IITF will commence from 14-27th Nov. 2017 at pragati Maidan New Delhi. It is annually organised mega trade show and is one of the biggest show ever made the history. India International Trade Fair (IITF) is the largest integrated trade fair with B2B and B2C components and has emerged as the largest trade fair in the Indian sub-continent.

The show will surely attract wide variety of buyers and sellers from nationally and internationally. It is being organised by Indian trade promotion organisation (ITPO)..

ITPO is the premier trade promotion agency of the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India

is committed to showcase excellence achieved by the country in diverse fields especially trade and commerce.

ITPO provides a wide spectrum of services to trade and industry and acts as a catalyst for growth of India's trade. ITPO approves holding of international trade fairs in India and regulates holding of various expositions in India primarily to avoid any duplication of efforts while ensuring proper timing. It manages India's world class exhibition complex which is constantly upgraded to keep it in a high standard of readiness. Spread over 123 acres of prime land in the heart of India's capital, New Delhi, Pragati Maidan offers about 61,290 sq. mtrs. of covered exhibition space in 16 halls, besides 10,000 sq. mtrs. of open display area. The state-of-the-art exhibition halls have enhanced the appeal of Pragati Maidan as the ideal center for an increasing number of fair organisers and business visitors from different parts of the world.

The IITF provides a platform for featuring the industrial and technological progress and also India's vast cultural heritage, intrinsic export potential and reforms. The fair has been tremendous significance for the Indian and foreign investors as it projects 25 sectors under "Make in India" as well as the Foreign Trade Policy schemes. It also aims to focus on steps for "Ease of Doing Business".

During the current year, 2016 as many as 7000 participants has taken part in the fair. The 'Partner Country' was 'South Korea' and the Focus Country was 'Belarus'. The Partner States are 'Madhya Pradesh' and 'Jharkhand' while Haryana is participating as the Focus State. There has been considerable increase in the foreign participants. Overseas participation is from Australia, Afghanistan, Belarus, Bahrain, Bangladesh, China, Germany, Hong Kong, Iran, Indonesia, Kuwait, Kyrgyzstan, Myanmar, Netherlands, Oman, Sri Lanka, South Africa, South Korea, Singapore, Tibet, Turkey, Thailand, UAE and UK.

Apart from featuring the state-of-the-art technologies, products, services and innovations



along with CSIR initiatives, the fair showcases immense variety and kaleidoscopic repertoire of India's handicrafts and handlooms with their multifarious uses, designs, motifs and techniques with diversity in both medium and method.

It is hoped that IITF 2017 will be more attractive and will be participated by more number of domestic enterprises as well as by foreign buyers with diversified range of products and ideas.

VI) Scope for SMEs:

The fair provides a reliable and tested platform to SMEs exporters, entrepreneurs and investors. Apart from highlighting initiatives on 'Digital India' of the Centre/ State Governments in their respective pavilions, the pavilions also projects first hand information about priceless collection of exquisite gems, architectural marvels built centuries ago, scenic hill stations, languid beach resorts, vibrant festivals, bountiful wild life, throbbing cities, lush tropical forests, timeless deserts, exhilarating adventure sports, ethnic handicrafts, impregnable forts and palaces and lots more.

VII) Event Participation by Development Commissioner (MSME):

Office of the Development Commissioner (MSME), Ministry of MSME is regularly participating in India International Trade Fair (IITF) since 2007. This year also there will be good participation of MSE,s under the sponsorship of DC(MSME). Interested MSE,s may apply on line for participation in IITF 2017.

Conclusion:-

Considering the significance of small and medium scale enterprise in Indian economy and in employment generation, Government of India, specially Ministry of MSME is focusing on promotion and development of MSME,s through various scheme/programme and policies as well through various support services. 'Cluster Development Programme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), Collateral Free Credit Guarantee

Scheme (CGS) for MSEs, National Manufacturing Competitiveness Program, Zero Defect Zero Effect (Z certification), National SC/ST Hub Scheme, Prime Minister Employment generation Programme and support through 18 Technology Centres (Tool Rooms & Technical Institutions) are some of the important initiative taken by the ministry of MSME to make the MSMEs globally competitive and also for economic development of the country. Marketing Assistance & technology upgradation Scheme (MATU) is one of the scheme of the ministry for providing marketing support to MSE,s which has been detailed in this article for the benefit of the MSE,s to avail the opportunities of the scheme.

MSME Clusters' have also been identified, based on the export potential of the product and the density of industries in the cluster for focused interventions to boost exports. Planning is also been made to organize outreach activities in a structured way in these clusters with the help of willing "Industry Partners" and "Knowledge Partners". This will specifically help in increasing exports from MSME sectors. Further, various steps being taken by the Govt. of India specially under MATU Scheme as well as showcasing of products/services by MSEs in such trade fair will definitely helpful to enhance the marketing of products/services including the export. However, there is a need to adopt latest technology and quality standard for manufacture of the products / providing services to meet the global challenges and to succeed in meeting the national goal of Make in India, Digital India, Skill India, Zero Defect and Zero Effect. These initiative will definitely help Indian industry to grow and meet the global challenges.

*– The writer is an Ex-Director (Chemical),
Office of DC (MSME).*



India's Rank Rises to 100 in World Bank's Doing Business Report, 2018

The World Bank, on 31st October, 2017 released the Doing Business (DB) Report, 2018. The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) is pleased to announce that India ranks 100 among 190 countries assessed by the Doing Business Team. India has leapt 30 ranks over its rank of 130 in the Doing Business Report 2017.

The DB Report is an assessment of 190 economies and covers 10 indicators which span the lifecycle of a business. The table below provides a comparison of this year's and last year's report. India has improved its rank in 6 out of 10 indicators and has moved closer to international best practices (Distance to Frontier score). The credit for this significant improvement is credited to the mantra of "Reform, Perform, Transform" given by the Prime Minister, wherein a strong leadership has provided the political will to carry out comprehensive and complex reforms, supported by a bureaucracy committed to perform. The Government has undertaken an extensive exercise of stakeholder consultations, identification of user needs, government process re-engineering to match Government rules and procedures with user expectations and streamlined them to create a more conducive business environment. An extensive exercise is also undertaken to increase awareness among users about reforms to ensure extensive use of newly created systems.

This edition of the report acknowledges India as a top improver, with an improvement of 30 ranks compared to last year's report, the highest jump in rank of any country in the DB Report, 2018. India is the only country in South Asia and BRICS economies to feature among most improved economies of the DB Report this year.

2. Major achievements in the World Bank in the Doing Business Report

The important highlights of India's performance are:

1. Resolving Insolvency -

- Rank improved from 136 to 103
- Distance to Frontier (DTF) score improved from 32.75 to 40.75
- Strength of insolvency framework index increased from 6 to 8.5
- Insolvency & Bankruptcy Code created for efficient handling of restructuring & insolvency proceedings
- Professional institutes set up for handling restructuring & insolvency proceedings

2. Paying Taxes -

- Rank improved from 172 to 119
- DTF score improved from 46.58 to 66.06
- Payments reduced from 25 to 13 in a year
- Time reduced from 241 to 214 hours
- Total tax rate reduced from 60.6% to 55.3% (% of profit)
- Post filing index improved from 4.3 to 49.31
- Enabled electronic registration, return & payment of ESI & EPF contributions

3. Getting Credit –

- Rank improved from 44 to 29
- DTF score improved from 65 to 75



- c. Strength of legal rights index improved from 6 to 8
 - d. Credit bureau coverage increased from 21.4% to 43.5% (% of adults)
 - e. Increased coverage of security interest registration under SARFAESI Act
 - f. Secured creditors prioritized over Government dues for purposes of recovery
- 4. Enforcing Contracts -**
- a. Rank improved from 172 to 164
 - b. DTF score improved from 35.19 to 40.76
 - c. Cost reduced from 39.6% to 31% (% of claim)
 - d. Quality of judicial process index improved from 9 to 10.3
 - e. Dedicated commercial courts established
 - f. National Judicial Data Grid (NJDG) to monitor and manage court cases
- 5. Protecting Minority Investors –**
- a. Rank improved from 13 to 4
 - b. DTF score improved from 73.33 to 80
 - c. Strength of minority investor protection index increased from 7.3 to 8
 - d. Extent of conflict of interest regulation index increased from 6.7 to 7.3
 - e. Extent of shareholder governance index increased from 8 to 8.7
 - f. Greater transparency requirements for interested parties transactions
 - g. Greater shareholder protection through action against directors & claims for damages
- 6. Construction Permits -**
- a. Rank improved from 185 to 181
 - b. DTF score improved from 32.83 to 38.80
 - c. Procedures to obtain construction permits reduced from 35.1 to 30.1
 - d. Time reduced from 190.0 to 143.9 days
 - e. Cost reduced from 25.9 per cent to 23.2 per cent of warehouse value. ■

Giriraj Singh launches MSME Delayed Payment Portal – MSME Samadhaan

Union Minister of State (Independent Charge) Shri Giriraj Singh launched MSME Delayed Payment Portal – MSME Samadhaan (<http://msefc.msme.gov.in>) on 30th October 2017, Empowering Micro and Small Entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to delayed payments by Central Ministries/Departments/CPSEs/State Governments. Shri Arun Kumar Panda, Secretary, Ministry of MSME along with other dignitaries and senior officials from the Ministry were also present.

Speaking on the occasion, Shri Giriraj

Singh said that the Micro, Small and Medium Enterprise Development (MSMED) Act, 2006 contains provisions to deal with cases of delayed payment to Micro and Small Enterprises (MSEs). As per the provisions, the buyer is liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on the amount at three times of the bank rate notified by Reserve Bank in case he does not make payment to the supplier for the supplies of goods or services within 45 days of the day of acceptance of the goods/service or the deemed day of acceptance.



Background:

The Portal will give information about the pending payment of MSEs with individual CPSEs / Central Ministries, State Governments, etc. The CEO of PSEs and the Secretary of the Ministries concerned will also be able to monitor the cases of delayed payment under their jurisdiction and

issue necessary instructions to resolve the issues. The portal will greatly facilitate the monitoring of the delayed payment in a more effective manner. The information on the portal will be available in public domain, thus exerting moral pressure on the defaulting organisations. The MSEs will also be empowered to access the portal and monitor their cases. ■

Vice President Inaugurates National SC/ST Hub (NSSH) Confluence

MOUs with 3 Sector Skill Councils to provide skill development trainings to SC/ST Entrepreneurs

The Vice President, Shri Venkaiah Naidu was the Chief Guest of National SC ST Hub (NSSH) Confluence organized by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and also released first ever radio jingle for National SC ST Hub. Minister of Social Justice & Empowerment Shri Thaawarchand Gehlot, Minister of Tribal Affairs Shri Jual Oram, Minister of State (Independent Charge), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Shri Giriraj Singh, Minister of State, Ministry of Finance Shri Shiv Pratap Shukla, were also present to grace the occasion.

The Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu has said that a collective, coordinated action is needed to strengthen the eco-system for promoting SC & ST Entrepreneurs in the country. He was addressing the National SC-ST Hub Confluence organized by the Union Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, on 20th September, 2017. The Union Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot, the Union Minister for Tribal Affairs, Shri Jual Oram, the Minister of State for Micro, Small & Medium Enterprises (I/C), Shri Giriraj Singh, the Minister of State for Finance, Shri Shiv Pratap Shukla and other dignitaries were present on the occasion.

The Vice President said that the country will

be developed when the downtrodden and under-privileged sections are uplifted. He further said that we need to have an integrated, multi-dimensional developmental agenda for the development of the country.

The Vice President said that setting up of Industries is important for the development of our country and it will solve the unemployment problem and increase the income. He further said that industry and agriculture are two important factors for the overall development of the country.

The Vice President while referring to the national discourse today, Stand-up, Start-up, Incubation, Innovation said that this should get further momentum and tempo. He further said that Make in India, Skill India, Digital India, Clean India – all these programmes should reach every section and everybody must get their due. Capacity building is important; credit availability is important, technology up-gradation is also important, he added.

The Vice President said that the Micro, Small and Medium Enterprise Sector (MSME) is the bulwark of the Indian economy and one of the largest employers after agriculture. He further said that it is also one of the major contributors to the country's GDP. With Make in India envisaging to



push contribution of the manufacturing sector to 25 per cent of the GDP by 2022, the MSME sector will be required to play a critical role in achieving the goal, he added.

The Vice President said that skill up gradation is one area that requires top attention for the overall development of SC/ST entrepreneurs. He congratulated the National SC/ST Hub for signing MoUs with Sector Skill Councils to skill over 2,000 entrepreneurs and said that the associations and incubators have a huge role to play in supporting the objectives of National SC/ST Hub. Each association must extend support in building capacities and mentoring entrepreneurs in its respective sector, he added.

Shri Shiv Pratap Shukla, Minister of State for Ministry of Finance, mentioned that Sabka Saath, Sabka Vikas is the genesis of the idea of inclusivity. He also promised his Ministry's full support to the Ministry of MSME to enable entrepreneurship amongst the SC ST community.

Shri Jual Oram, Minister of Tribal Affairs stated that he was glad that the Government has taken an initiative as unique as NSSH to uplift the ST community of the country.

Shri Thaawarchand Gehlot, Minister of Social Justice & Empowerment mentioned that all MSMEs face challenges in marketing their products due to competition from large enterprises which is why the Public Procurement Policy is a welcome step.

Shri. Giriraj Singh, Minister of State (Independent Charge), Ministry of MSME thanked everyone for their presence and mentioned that if SC ST entrepreneurs can get orders worth Rs. 5,000 crores, it will go a long way in helping such entrepreneurs. He mentioned that the day the job seeker becomes a job giver, dreams of everyone shall be accomplished.

Dr. Arun Kumar Panda, Secretary, Ministry of MSME highlighted that the programme was a medium to build bridges therefore connecting everyone and bringing everyone on a common

platform. A brief presentation was given by Joint Secretary, SME, on the initiatives undertaken by the hub, highlighting the progress till date.

The confluence brought various insights from Industry Association and Incubators to understand the gaps in realizing the mandate of Public Procurement Policy and put forth innovative strategies for holistic development of MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. The discussion held was extremely fruitful and intend to go a long way in meeting the objectives of the National SC ST Hub.

Interactive session was held with over 150 industry associations and incubators with representation of over 400 participants, focussing on collaboration with NSSH, to augment the capabilities of existing SC/ST entrepreneurs. Several excellent suggestions were made with respect to market access; capacity building, tender challenges, technology upgradation, etc. were made. The session also focused on future action plan along with role to be played by each stakeholder to achieve the objectives of the hub.

In addition, MOUs were signed with 3 Sector Skill Councils to provide skill development trainings of SC-ST Entrepreneurs under capacity building initiatives of NSSH.

Background:

The Government of India formulated the Public Procurement Policy, 2012 which states that 20% of total procurement of goods and services by Central Ministries, Departments and CPSEs shall be made from MSEs and 20% of such procurement (4% of total) shall be from SC & ST owned MSEs.

NSSH is a unique initiative launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 18th October 2016. This initiative is aimed empowering SC ST owned MSEs in order to achieve the 4% mandate of the Public Procurement Policy.

In view of the above, the NSSH initiative has the potential to work on ground and have an impact till the last mile. Due to the social and economic



bearing the programme can have, it requires a strategy that delivers sustained and measureable impact, on the entire MSME ecosystem. Therefore, there have been continual efforts to include all relevant stakeholders including state, industry associations, incubators, CPSEs to identify synergies and work collaboratively and cohesively towards a shared goal.

Some of the milestones achieved by the hub are as follows -

1. Data analysis completed for 5 lakh SC/ST units to identify suppliers to CPSEs
2. Physical verification of over 4,900 SC/ST entrepreneurs completed that had potential to supply to CPSEs
3. Telephonic interaction with over 2,590 SC/ST MSMEs completed to understand challenges in securing PSUs' tenders
4. Information of 1,003 SC/ST enterprises mapped with 42 CPSEs for vendor empanelment and procurement
5. Appointment of nodal officers in 67 CPSEs. Discussion with over 60 CPSEs conducted
6. Special Marketing Assistance Scheme - 950 units participated in domestic and international fairs/exhibition
7. 2,107 units facilitated with CPSE linkages under Special Vendor Development Programme
8. 512 SC/ST units benefitted under Special Performance & Credit Rating Scheme
9. Training programme conducted in IIM Noida (Satellite institute of IIM Lucknow), IIM Lucknow, IIM Raipur, IIM Kolkata and XLRI Jamshedpur (on pilot basis) for SC/ST entrepreneurs for over 100 SC/ST entrepreneurs.

Key highlights of the discussion were:

1. Getting support from Industry Associations

on data consolidation and Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) registration.

2. Providing on ground support to adopted SC-ST owned MSEs by Industry Associations and Incubators.
3. Assisting NSSH in future endeavours in spreading awareness by participating, organizing various events, seminars, workshops, knowledge sessions etc.
4. Mentoring and handholding support to potential SC-ST entrepreneurs during and post incubation programme.
5. Providing capacity building trainings to SC-ST Entrepreneurs.
6. Technology collaboration with overseas partners is required to upgrade existing technology

The following suggestions were made -

1. While releasing tenders, CPSEs should focus on quality based products manufactured by MSMEs, especially SC-ST entrepreneurs rather than established brands.
2. It was proposed that there is a need to create awareness around the various schemes of the Government in addition to the NSSH
3. It was suggested that the prequalification criteria for CPSE tenders should be eliminated for SC ST MSEs.
4. For VDP programmes, it was suggested that instead of conducting the VDPs in neutral locations, these should be done at the premises of the respective CPSEs.
5. It was proposed, that sanctioned loan tenure should be extended to provide sustainable support to SC ST MSEs.
6. It was suggested that traditional businesses like Handicraft sector, Leather sector etc. needs to be promoted and requires government's intervention for growth and development. ■



Evaluation study of Prime Minister's Employment Generation Programme

Minister of State (Independent Charge) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Shri Giriraj Singh was presented with Evaluation Study of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) conducted by Management Development Institute (MDI), Gurugram. The institute was entrusted with the task of conducting Evaluation Study of PMEGP in January, 2017.

The aim of the study was examine the impact of the scheme in terms of employment generation and improvement in income of the rural and urban artisans and unemployed youth, major problems in implementation of Scheme and ways to resolve them and to make recommendations on making further improvements in the Scheme.

The sample size was selected on stratified random sampling basis. The total number of micro units setup from 2012-013 to 2015-16 was 2,00,885 units. This units were taken into consideration, out of these a sample coverage of 5% i.e. about 10,108 units were sought listed on random basis from among the three implementing agencies viz. KVIC, KVIB and DIC in proportion of 30:30:40.

Key observations of the Study:

Scheme has been able to provide Sustainable Employment. Units set up under the scheme provided employment throughout year and for large number of years.

Scheme has good reach, it has targeted at almost all sections of the society (based on social background, education background, location etc)

Average Employment Per Project	–	7.62
Average Cost of Generating Unit Employment	–	96,209

Maximum Cost of Generating Unit Employment	–	2,75,621 (Nagaland)
Minimum Cost of Generating Unit Employment	–	64,735 (Tamil Nadu)
Average Cost per Project	–	7,33,423

Problem Areas:

- Delay in the process of sanctioning of loans at different stages.
- Hypothecation & collaterals asked for.
- Physical verifications & delay in adjustment of margin money.
- Records keeping, hand holding, access of data & reporting by implementing agencies.
- Marketing for products.

Key recommendations:

Increased availability of field officers (They are a key connect between beneficiary and agencies and are currently sparse)

EDP Training content needs to be more relevant and rigorous. On line EDP could be encouraged.

Content partnership/Integration with MOOCs (Massive Open Online Coursewares) of recognized reputational technical and managerial institutes (such as IITs and IIMs)

Agencies could consider hiring interns from leading management institutions (India/Abroad) to further handholding of beneficiaries

Integration with Aadhar to authenticate the

trainee identity and progress.

For motivating beneficiaries to repay loans – The people whose Margin Money has been successfully adjusted, need to be rewarded with an option of 2nd round of subsidized loans (at say 15% of subsidy).

Enforcement of deadlines (either of 60 or 90 days) on banks to decide about decision (acceptance or rejection) of the loan application

viii. Cash credit account (CCA) component of the loan could be reduced. Maximum CCA may range up to 40% of total loan ■

Secretary reviews implementation of Public Procurement Policy by various PSUs in National SC/ST Hub Conclave

National SC/ST Hub Conclave was chaired by Dr. Arun Kumar Panda, Secretary, Ministry of MSME, and other senior officials of the ministry were present on the occasion. Chairman or representatives from about 50 PSUs from 20 Ministries also participated in the conclave.

The interaction aims to bring together leading CPSEs from different sectors and initiate discussion to understand the gaps and their challenges in realizing the mandate of Public Procurement Policy. The interaction is envisioned to put forth a strategy that delivers sustained and measurable impact on the entire MSME ecosystem. With participation from over 50 CPSEs from 20 Ministries, the conclave also aims to develop an understanding of procurement requirements of CPSEs and facilitating them in vendor development programme by providing support in mobilizing SC/ST entrepreneurs.

Ministry of MSME, through National SC-ST Hub, is continuously thriving to achieve its objectives, and in order to accomplish desired goals has taken up multiple initiatives. The conclave will give a brief on all ongoing activities and also give a snapshot on the roadmap for the near future.

A brief presentation by Joint Secretary, MSME, on the achievements and challenges faced by CPSEs in procuring goods and services from SC/ST entrepreneurs was given. In order to receive inputs and suggestions from CPSEs, an open discussion

was organized during the conclave to decide upon the future course of action. Key highlighted from the discussion were:

1. Current status of procurement done by CPSEs from MSMEs (including SC/ST MSEs) during the last Financial Year
2. Need for one consolidated database of SC/ST Vendors including details of products and services provided by them
3. Focus on organizing Special – Vendor Development Programmes (VDPs) and capacity building programmes for addressing the skills gap of SC/ST MSEs
4. Use of technology as a medium for dissemination of information

The conclave brought various insights from CPSEs to understand the gaps in realizing the mandate of Public Procurement Policy and put forth innovative strategies for holistic development of MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. The discussion help was extremely fruitful and will go a long way in meeting the objectives of the National SC/ST Hub

Background:

National SC-ST Hub, launched by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, aims to create a supportive ecosystem for SC/ST entrepreneurs by assisting in technology upgradation and capacity



building thereby enabling them to effectively participate in public procurement processes. The Government of India formulated the Public Procurement Policy, 2012 which states that 20% of total procurement of goods and services by Central

Ministries, Departments and CPSEs shall be made from MSEs and 20% of such procurement (4% of total procurement) from MSEs shall be made from SC & ST owned MSEs. ■

GST on Khadi products

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) welcomes the introduction of GST. The entire Khadi & Village Industries (KVI) sector has been enjoying the benefit of tax exemption even under the pre-independence era. With the exemption to the SSI sector being drastically reduced from the existing Rs. 150 lakh to Rs. 20 lakh, the exemption cover enjoyed by many of the Khadi Institutions (KIs) has been removed. KIs are now mandated to obtain registration under GST and also pay GST on various Khadi products which is 5%. The products of the Village Industries sector were either taxed @ 0-14.30% before-GST and post-GST the same products attracts tax @ 12-28%, and the details of the same is given below:

Details of products of the Village Industries sector under pre-GST & post-GST

Items	Before (GST)	After (GST)
Dona plate	5%	18%
PVC Scrap	5%	18%
Ayurvedic Medicine	0%	12%
Sanitary Hardware & Paint	14%	28%
Marble & Granite	5-14%	28%
Electronic Weighing Scale	5.5%	28%
Lock	5%	18%
Mentha	5%	18%
Solar Plate	0%	18%
Textile sector	0 to 5%	18%
Gobar Gas/Bio Fuel Generator	0%	18%

Items	Before (GST)	After (GST)
Agriculture Diesel Engine (upto 12 B.H.P.)	5%	28%
Plywood	14.30%	28%
Sewing Machine parts	5%	12%
Detergents	5%	28%
Glassware boll (Kancha)	0%	18%
Tractor attachments	14%	28%
Weighing machines	14%	28%
Wet grinders	14%	28%
Compressors	14%	28%
Packing Machines	14%	28%
Auto-parts	14%	28%
Garage Equipment	14%	28%
Hand-made soap (3401)	0%	18%
Hand-made paper (4802)	0-4%	12%
Herbal Shampoo (3305)	5-12%	28%
Leather Products (suit-case/brief-case/other articles)	5-12%	28%
Agricultural, Horticultural or Forestry Machinery for Soil preparation	5%	12%
Harvesting or threshing machinery	0%	12%
All food mixes, sharbat, ready to eat packaged food	5%	18%



Items	Before (GST)	After (GST)
Hand operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink	5%	18%

At present only Khadi yarn produced in Khadi sector is exempted, while other Khadi products

attracts 5% GST. Ministry of MSME has approached Ministry of Finance to consider the sector for exemption from GST or to ensure a seamless flow of input tax credit in order for Khadi Institutions to claim input tax credit.

This Press Release is based on information given by the Minister of State for MSME Shri Giriraj Singh in a written reply to a question in Rajya Sabha on 10.08.2017. ■

Creation of employment opportunities through MSMEs

The Micro, Small and Medium Enterprises play an important role in creating employment opportunities in the country. As per the last Census (Fourth) of Micro, Small and Medium Enterprises data collected with reference to base year 2006-07, as well as data extracted from the Economic Census 2005 conducted by Central Statistical Office (CSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), for activities excluded from Fourth Census, namely wholesale/

retail trade, legal, educational and social services, hotel & restaurants, transports and storage & warehousing (except cold storage), the total employment in the MSME sector was 805.24 lakh.

Details of targets fixed and achieved in respect of employment generation under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) during the last three years and the current year in the country is given below:

	Target for employment generation				Estimated employment generated			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
All India	703492	516232	434758	406272	357502	323362	407840	150616

*(as on 31.10.2017)

Following initiatives have been taken to achieve the targets under PMEGP Scheme:

In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management and to prevent parking of funds at Nodal bank level an online PMEGP-MIS web portal has been introduced. All applications and fund flow is processed online in stipulated time frame.

Publicity is being made through print and electronic media, awareness camps at District level

and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro industries.

Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.

For speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs as per MOU executed between KVIC & MCR.



Industries such as Khadi, processing of Pashmina Wool, handloom and power loom units, value added products for tea, coffee, rubber etc. and transport activities are now eligible for assistance under PMEGP.

This Press Release is based on information given by the Minister of State for MSME Shri Giriraj Singh in a written reply to a question in Rajya Sabha on 10.08.2017. ■

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

P rime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. Any individual above 18 years of age is eligible. For setting up of projects costing above Rs. 10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business/service sector, the beneficiaries should possess at least VIII standard pass educational qualification. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /

minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas.

The Scheme was launched during 2008-09. A total of 4.23 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs. 8695.27 crore providing employment to an estimated 35.48 lakh persons since 2008-09 till 2016-17 across the country including the State of Maharashtra.

The State/UT-wise details of number of micro units setup and Margin Money disbursed under PMEGP during the last two years is given as Annexure-I.

Details of the target fixed/achieved during last three years in Maharashtra State are as follows:

(Rs. In lakh)

Year	Target			Achievement		
	Projects	Margin Money	Employment Generation	Projects	Margin Money disbursed	Employment Generated
2015-16	4860	9718.42	38880	2497	5285.03	20161
2016-17	3056	6111.30	24448	2325	6001.3	17799

Following steps have been taken by the Government for effective implementation of PMEGP Scheme and achieving the targets:

In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management and to prevent parking of funds at Nodal bank level an online PMEGP-MIS web portal has been introduced. All applications and fund flow will be processed

online in stipulated time frame.

Publicity is being made through print and electronic media, awareness camps at District level and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro industries. Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units. For



speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs as per MOU executed between KVIC & MCR. Industries such as Khadi, processing of Pashmina Wool, handloom and power loom units, value added products for tea,

coffee, rubber etc. and transport activities are now eligible for funding under PMEGP.

This Press Release is based on information given by the Minister of State for MSME Shri Giriraj Singh in a written reply to a question in Rajya Sabha on 02.08.2017. ■

Mahila Coir Yojana

The Coir Board is implementing Mahila Coir Yojana (MCY) exclusively for empowering women in the country by giving training and distribution of coir processing equipments. This is a 100% women oriented programme intended to provide self employment to the rural women artisans in coir producing regions. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments, which can be operated by women, at 75% subsidy after imparting training with a duration of 2 months subject to a maximum amount of Rs. 7,500/-. The training under MCY are conducted through all training centres of the Board. During the training period, the women artisans are given stipend amounting to Rs.1000 per month. The scheme is

prevalent in coir producing coastal States such as Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Lakshadweep, Maharashtra, Gujarat, Goa, Pondicherry, A & N Islands, West Bengal and NE Region. During the current year the targets of 1000 women for training and 200 ratts/equipments for distribution to the trained women have been fixed under MCY and an amount of Rs. 35.00 lakhs have been allocated for the current year. Coir Board has received 97 applications under the Scheme and all the applications are from Kerala only.

This Press Release is based on information given by the Minister of State for MSME Shri Giriraj Singh in a written reply to a question in Lok Sabha on 31.07.2017. ■

MSME Hubs

The Ministry of MSME has not established or proposed to establish Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) hubs/zones in the country. However, this Ministry has approved a scheme for setting up of National Scheduled Caste and Scheduled Tribes (SC/ST) Hub on 25.07.2016. Hon'ble Prime Minister launched the National SC/ST Hub on 18.10.2016 at Ludhiana, Punjab. The National SC/ST Hub is being implemented through the National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC). The Hub is set up to provide professional support to SC/ST entrepreneurs to fulfill the obligations under the Central Government Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order 2012, adopt applicable business practices and leverage the Stand up India initiatives. The functions of Hub

include collection, collation and dissemination of information regarding SC/ST enterprises and entrepreneurs, capacity building among existing and prospective SC/ST entrepreneurs through skill training and EDPs, vendor development involving CPSEs, NSIC, MSME-DIs and industry associations including Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry (DICCI), promoting participation of SC/ST entrepreneurs in exhibitions and organizing special exhibitions for this purpose, facilitating SC/ST entrepreneurs participating in public procurement and monitoring the progress, etc.

This Press Release is based on information given by the then Minister of State for MSME Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary in a written reply to a question in Lok Sabha on 17.07.2017. ■



ZED Scheme for MSMEs

The Government has launched a new scheme namely “Financial Support to MSMEs in ZED Certification Scheme”.

The objective of the scheme for promotion of Zero Defect and Zero Effect (ZED) manufacturing amongst micro, small and medium enterprises (MSMEs) and ZED Assessment for their certification so as to:

- Develop an Ecosystem for Zero Defect Manufacturing in MSMEs.
- Promote adaptation of Quality tools/systems and Energy Efficient manufacturing.
- Enable MSMEs for manufacturing of quality products.
- Encourage MSMEs to constantly upgrade their quality standards in products and processes.
- Drive manufacturing with adoption of Zero Defect production processes and without impacting the environment.
- Support ‘Make in India’ campaign.
- Develop professionals in the area of ZED manufacturing and certification.

There are 50 parameters for ZED rating and additional 25 parameters for ZED Defence rating under ZED Maturity Assessment Model. The MSMEs are provided financial assistance for the activities to be carried out for ZED certification i.e., Assessment / Rating, Additional rating for Defence angle, Gap Analysis, Handholding, Consultancy for improving the rating of MSMEs by Consultants and Re-Assessment / Re-Rating.

Under the scheme 22,222 MSMEs will be rated & certified under ZED Maturity Assessment Model, 5,000 MSMEs will be rated & certified under the ZED Defence Model, 7368 MSMEs will be supported for Gap Analysis, Handholding, Consultancy for improving their rating, etc. The total

cost of the project is Rs. 491.00 crores (Government contribution Rs 365.00 crores, beneficiary MSMEs contribution Rs 126.00 crores).

Quality Council of India (QCI) has been appointed as the National Monitoring & Implementing Unit (NMIU) for implementation of ZED. 5802 MSMEs have been registered as on 19.11.2017 for ZED Certification. The MSME-wise details are Micro: 2427, Small: 2657 & Medium: 572 and financial assistance to MSMEs is yet to commence. 30 Assessment have been completed. 16029 MSME got Gold, Silver & Bronze recity respecting.

The Ministry of MSME is implementing a number of schemes to promote MSMEs namely (i) Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises to facilitate collateral free credit to new and existing micro and small enterprises (MSEs); (ii) Scheme for Raw Material Assistance implemented by National Small Industries Corporation Limited under the Ministry; (iii) National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) and Credit Linked Capital Subsidy Scheme implemented to facilitate upgradation of technology, improve processes and design; (iv) Management Development Training Programmes (MDPs) for enhancing managerial skills; (v) Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme to facilitate infrastructure upgradation and setting up of Common Facility Centres; and (vi) Marketing Development Assistance Support to MSME; (vii) Ministry of MSME has introduced online MSME Data Bank on 29.07.2016 for creating comprehensive database of MSMEs and (viii) Ministry of MSME has introduced simplified online registration “Udyog Aadhar Memorandum (UAM) for MSMEs”. 33,25,159 MSMEs registered with UAM from September, 2015 till 25.07.2017.

This Press Release is based on information given by the then Minister of State for MSME Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary in a written reply to a question in Lok Sabha on 31.07.2017. ■



ECO MARK Label on Coir Products

The importing countries are well aware of the eco-friendliness of the Coir and Coir product. The Coir industry is very much in need of the Eco Labeling for its products which will definitely boost its marketing potential both abroad and within the country. The Coir Board has already taken up the matter of obtaining ECO MARK for coir products with the Ministry of Environment and Forest and is constantly pursuing it for finalizing the criteria for obtaining the ECO Mark.

The Eco Mark Labeling for coir and coir products will boost the exports of these products in view of the growing affinity towards natural/eco-friendly products in the international market. The Government through the Coir Board is implementing schemes for promotion of coir in

the country which also contributes to enhance export of coir and coir products. In particular, the Export Market Promotion Scheme under Coir Vikas Yojana (CVY) provides for adoption of product specific and market specific promotional activities for popularizing coir and coir products in overseas markets, supporting export oriented coir units on modernization, etc. The interventions under the Scheme also include market survey, consultancy, data sourcing, participation in international events and financial assistance to entrepreneurs to participate in international fairs.

In addition to incentives under the Merchandise Export from India Scheme (MEIS), Coir products are also eligible to get fiscal incentives under Duty Drawback Scheme ranging from 1–5%. ■

Development of MSMEs

The Ministry on 18.09.2015 has notified for online filing of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) at <http://udyogaadhaar.gov.in> by MSMEs in place of existing Entrepreneurs Memorandum-II. State/UT wise number of registered Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) under Entrepreneur Memorandum-II (EM-II) and Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) during the last three years and current year are given in Annexure-I. Units registered under EM-II during 2007-15 (Nine years period) were 21,96,902, whereas units registered under UAM from September, 2015 to till date were 32,72,412 (One Year and Ten months period).

As per the fourth All India Census for MSMEs conducted in 2006-07, for the period ending on 31.3.2007 a total of 4,96,355 registered units in the country were closed out of which 80,616 units were related to State of Uttar Pradesh. State/UT wise number of closed units are given at Annexure-

II.

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has been implementing various schemes and programmes for development and promotion of Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) across the country. The major schemes / programmes include Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSECDP), Performance & Credit Rating Scheme, Marketing Assistance scheme, International Cooperation Scheme, Assistant to Training Institutions etc. All plan schemes implemented by Ministry of MSME are Central Sector Schemes. Therefore, funds are not allocated State-wise, under these schemes. However, the details of fund allocated and utilized under various schemes of the Ministry at all India



level during the last three years and the current are, as under:-

(Rs. crore)

Year	Budget Allocation (BE)	Actual Expenditure
2014-15	3327.00	2389.90
2015-16	2612.51	2440.56
2016-17	3000.00	3173.00
2017-18	6481.96	1963.48*

*upto 07.07.2017

Annexure-I

Annexure-I referred to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 49 for answer on 17.07.2017

SL. No.	State	Units registered under EM-II	Units registered under UAM since 18.09.2015			
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
1.	Andhra Pradesh	2810	9736	161667	26608	
2.	Arunachal Pradesh	25	60	249	63	
3.	Assam	2629	36	916	396	
4.	Bihar	2009	98725	551946	37903	
5.	Chhattisgarh	1702	4760	6512	1302	
6.	Goa	160	786	1154	261	
7.	Gujarat	64160	52046	194852	57717	
8.	Haryana	1482	4537	23746	9017	
9.	Himachal Pradesh	388	1036	2006	519	
10.	Jammu And Kashmir	1159	58	2538	203	
11.	Jharkhand	3450	21045	49716	5554	
12.	Karnataka	28754	14168	47729	14533	
13.	Kerala	14906	11313	23216	4453	
14.	Madhya Pradesh	19903	39600	87078	22580	
15.	Maharashtra	36992	54671	209444	33157	
16.	Manipur	198	1712	6525	1414	

SL. No.	State	Units registered under EM-II	Units registered under UAM since 18.09.2015		
17.	Meghalaya	118	1	330	100
18.	Mizoram	278	1	385	309
19.	Nagaland	91	12	170	21
20.	Odisha	2995	9849	42204	5768
21.	Punjab	2137	4796	20966	6871
22.	Rajasthan	18655	34050	102125	34785
23.	Sikkim	7	49	115	37
24.	Tamil Nadu	143104	41651	267498	58267
25.	Telangana	5787	20770	57867	10715
26.	Tripura	172	516	1311	174
27.	Uttar Pradesh	52203	45158	401400	44456
28.	Uttarakhand	2669	1777	4986	1336
29.	West Bengal	15244	16449	81628	13435
30.	Andaman And Nicobar Islands	112	519	1060	340
31.	Chandigarh	160	273	1403	415
32.	Dadar And Nagar Haveli	90	244	711	182
33.	Daman And Diu	56	179	436	91
34.	Delhi	652	7800	20050	5361
35.	Lakshadweep	5	10	18	2
36.	Puducherry	96	303	1731	426
	Total:-	425358	498696	2375688	398771

*As on 13.07.2017

Annexure-II

Annexure-II referred to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 49 for answered on 17.07.2017

S. No.	Name of the States/UTs	No. units closed
1.	Andaman & Nicobar	142
2.	Andhra Pradesh	2250
3.	Arunachal Pradesh	167
4.	Assam	6266
5.	Bihar	16344



S. No.	Name of the States/UTs	No. units closed
6.	Chandigarh	559
7.	Chhattisgarh	15485
8.	Dadra & Nagar Haveli	0
9.	Daman & Diu	24
10.	Delhi	0
11.	Goa	2754
12.	Gujarat	34945
13.	Haryana	10973
14.	Himachal Pradesh	4034
15.	Jammu & Kashmir	1831
16.	Jharkhand	3712
17.	Karnataka	47581
18.	Kerala	34903
19.	Lakshadweep	0
20.	Madhya Pradesh	36502
21.	Maharashtra	41856
22.	Manipur	929
23.	Meghalaya	665

S. No.	Name of the States/UTs	No. units closed
24.	Mizoram	669
25.	Nagaland	2395
26.	Orissa	5744
27.	Puducherry	711
28.	Punjab	24553
29.	Rajasthan	17342
30.	Sikkim	86
31.	Tamilnadu	82966
32.	Tripura	424
33.	Uttar Pradesh	80616
34.	Uttarakhand	8219
35.	West Bengal	10708
	All India	496355

This Press Release is based on information given by the then Minister of State for MSME Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary in a written reply to a question in Lok Sabha on 17.07.2017. ■

Performance of NMCP

National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) seeks to enhance the competitiveness of manufacturing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through following interventions:

- Lean Manufacturing Competitiveness Scheme (LMCS)
- Design Clinic Scheme,
- Technology & Quality UP-gradation support for MSMEs (TEQUP)
- Digital MSME Scheme,
- Building Awareness on Intellectual Property
- Enabling Manufacturing Sector to be Competitive through Quality Management

Standards (QMS) and Quality Technology Tools (QTT) (This component has been subsumed under Zero Defect Zero Effect (ZED) Certification scheme.

- Entrepreneurial & Managerial Development of SMEs through incubators

(The growth of any enterprise including MSMEs depends upon various factors within and outside the enterprise. The NMCP is designed to increase their competitiveness through the aforesaid interventions which are by and large soft interventions. Thus, NMCP interventions are only one of the factors that contribute to the growth of MSMEs.

Budget allocation for NMCP during last 5 years (from 2012-13 to 2016-17) is Rs. 429.50 crores.



NMCP is a demand driven programme designed to make MSMEs competitive in domestic and international markets as per the approved guidelines of its various interventions. There are enabling provisions for providing professional consultants and expert agencies to MSMEs in NMCP components like LMCS, Design etc. Moreover,

financial assistance is also made available for acquisition of energy efficient technology.

This Press Release is based on information given by the then Minister of State for MSME Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary in a written reply to a question in Lok Sabha on 17.07.2017. ■

Vigilance

Important Features of the 'Whistle-Blowers' Resolution

- The CVC shall, as the Designated Agency, receive written complaints or disclosure on any allegation of corruption or of mis-use of office by any employee of the Central Government or of any corporation established under any Central Act, government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government.
- The designated agency will ascertain the identity of the complainant; if the complainant is anonymous, it shall not take any action in the matter. · The identity of the complainant will not be revealed unless the complainant himself has made either the details of the complaint public or disclosed his identity to any other office or authority.
- While calling for further report/investigation, the Commission shall not disclose the identity of the informant and also shall request the concerned head of the organisation to keep the identity of the informant a secret, if for any reason the head comes to know the identity.
- The Commission shall be authorised to call upon the CBI or the police authorities, as considered necessary, to render all assistance to complete the investigation pursuant to the complaint received.
- If any person is aggrieved by any action on the ground that he is being victimised due to the fact that he had filed a complaint or disclosure, he may file an application before the Commission seeking redress in the matter, wherein the Commission may give suitable directions to the concerned person or the authority.
- If the Commission is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, it shall issue appropriate directions to the concerned government authorities.
- In case the Commission finds the complaint to be motivated or vexatious, it shall be at liberty to take appropriate steps.
- The Commission shall not entertain or inquire into any disclosure in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants Inquiries Act, 1850, or a matter that has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952.
- In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of the Commission's directions to the contrary, it is authorised to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or agency making such disclosure. ■

– Source : CVC



GOI Resolution in Public Interest Disclosure and Protection of Informer

1. The Government of India has authorized the Central Vigilance Commission (CVC) as the 'Designated Agency' to receive written complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action.

2. The jurisdiction of the Commission in this regard would be restricted to any employee of the Central Government or of any corporation established by or under any Central Act, government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government. **Personnel employed by the State Governments and activities of the State Governments or its corporations etc. will not come under the purview of the commission.**

3. In this regard, the Commission, which will accept such complains, has the responsibility of keeping the identify of the complainant secret. **Hence, it is informed to the general public that any complaint, which is to be made under this resolution should comply with the following aspects.**

- The complaint should be in a **closed / secured envelope**.
 - the envelope should be addressed to Secretary, Central Vigilance Commission and should be **superscribed "Complaint under The Public Interest Disclosure"**. If the envelope is not superscribed and closed, it will not be possible for the Commission to protect the complainant under the above resolution and the complaint will be dealt with as per the normal complaint policy of the Commission. The complainant should give his/her name and address in the beginning or end of complaint or in an attached letter.
 - Commission will **not entertain anonymous/pseudonymous complaints**.
 - The text of the complaint should be carefully drafted so as **not to give any details or clue as to his/her identity**. However, the details of the complaint should be specific and verifiable.
 - In order to protect identity of the person, the Commission will not issue any acknowledgement and the whistle-blowers are **advised not to enter into any further correspondence** with the Commission in their own interest. The Commission assures that, subject the facts of the case being verifiable, it will take the necessary action, as provided under the Government of India Resolution mentioned above. If any further clarification is required, the Commission will get in touch with the complainant.
4. The Commission can also take **action against complainants making motivated/vexatious complaints** under this Resolution.
5. A copy of detailed notification is available on the web-site of the Commission <http://www.cvc.nic.in>.

– Issued in Public Interest by the Central Vigilance Commission, INA, Satarkta Bhawan, New Delhi.

Sd/-
Secretary
Central Vigilance Commission

लघु उद्योग समाचार (द्विभाषी मासिक)

ग्राहक बनने के लिए सम्पर्क करें:

मासिक पत्रिका 'लघु उद्योग समाचार' के सामान्य अंक की एक प्रति का मूल्य 20 रुपए और विशेषांक का मूल्य 25 रुपए है, जबकि वार्षिक मूल्य 250 रुपए है। वार्षिक शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में सीधे प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 को भेजा जा सकता है। पत्रिका नकद भुगतान पर प्रकाशन नियंत्रक कार्यालय के विभिन्न बिक्री केंद्रों से भी खरीदी जा सकती है।



लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
जुलाई/July, 2016

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

Focus on
Public Procurement

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
अगस्त/August, 2016

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

Focus on
● Innovation
● MSMEs in Punjab

Special Issue

40 YEARS OF LAGHU UDYOG SAMACHAR
1976-2016

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
सितंबर/September, 2016

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

Focus on
National Awards

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
अक्टूबर/October, 2016

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

Special Issue

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
नवम्बर/November, 2016

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

▶ हिन्दुस्तान सर्वोत्तम देश बनाने में अपने चरम परानी इकोनॉमी
▶ सूक्ष्म और लघु उद्योगों में कामकाज काफ़ी विद्यमान
▶ जीवन का मंत्र है खादी फॉर फैशन
- जेठू मोदी

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
दिसम्बर/December, 2016

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

नववर्ष की शुभकामनाएं
2017
Happy New Year

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
जनवरी/January, 2017

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

Special Issue on
Women Entrepreneurs

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
फरवरी-मार्च/February-March, 2017

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

MSME BUDGET

● Interview of Union Minister of MSME

लघु उद्योग समाचार
Laghu Udyog Samachar
अप्रैल-मई/April-May, 2017

MSME
महान, लघु एवं मध्यम उद्यम
Micro, Small & Medium Enterprises

GST & MSME

● New Scheme : Digital MSME
● Achievements : Ministry of MSME

GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

MSE-CDP
Micro and Small Enterprise Cluster Development programmes for holistic development of selected MSEs clusters through value chain and supply chain management on co-operative basis

 <p>Prime Minister Employment Generation Programme(PMEGP)</p> <p>A credit linked Scheme to facilitate participation of financial institutions for higher credit flow to micro sector. Its objectives are to generate continuous and sustainable employment opportunities in Rural and Urban areas of the country through start-ups.</p> <p>Read more...  </p>	 <p>National Manufacturing Competitiveness Programme</p> <p>To promote growth oriented enterprise through 10 interventions like lean manufacturing, design clinic, quality management systems etc.</p> <p>Read more...  </p>	 <p>ASPIRE</p> <p>To promote Innovation & Rural Entrepreneurship through rural livelihood incubator, technology business incubator and fund of funds To establish Technology Centre Network to promote Innovation, Entrepreneurship and Agro-Industry, I propose to set up a fund with a corpus of Rs. 200 crore." 105B."</p> <p>Read more...  </p>	 <p>Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries(SFURTI)</p> <p>Making traditional Industries more productive and competitive by organizing the traditional Industries and artisans into clusters.</p> <p>Read more...  </p>
 <p>Performance & Credit Rating Scheme</p> <p>To create an eco-system of MSEs for easier/ cheaper access to credit for the rated enterprises. The rating done for MSEs generates an awareness about the strengths and weaknesses of the operations and creditworthiness of the enterprise.</p> <p>Read more...  </p>	 <p>Assistance to Training Institution</p> <p>To promote entrepreneurship and skill development through capital grant for creation/strengthening of infrastructure and programme support for conducting entrepreneurship development and skill development programmes</p> <p>Read more...  </p>	 <p>Marketing Assistance</p> <p>To assist MSMEs to organise/ participate in exhibition of their products and services in domestic and global markets. Organizing Buyer-Seller Meets, Intensive Campaigns and Marketing Promotion Events are also included</p> <p>Read more...  </p>	 <p>Credit Linked Capital Subsidy Schemes(CLCSS)</p> <p>To enable micro and small enterprises to adopt modern technology to improve their productivity</p> <p>Read more...  </p>

dcmsme.gov.in udyogaadhaar.gov.in msme.gov.in pmindia.gov.in mygov.in